

जन जन की बात जन जन तक

साप्ताहिक

जन जन विचार



WEEKLY TRILINGUAL NEWSPAPER

Language : Hindi, Assamese & English

WEBSITE : www.janjanvichar.in

VOICE OF ALL, FOR ALL

WEEKLY

JAN JAN VICHAR

বাইজৰ কথা বাইজৰ মাজলৈ

সাপ্তাহিক

জন জন বিচাৰ

RNI Regd No. ASMUL/25/A2367::Guwahati, Friday, 13 November 2026 :: Year-1 Vol-44 Issue-23 :: शुक्रवार। 13 नवंबर 2026। शाक संवत 1948। कार्तिक। शुक्ल। चतुर्थी। :: पृष्ठ-20। मूल्य-15 रुपए

जन चिंतन

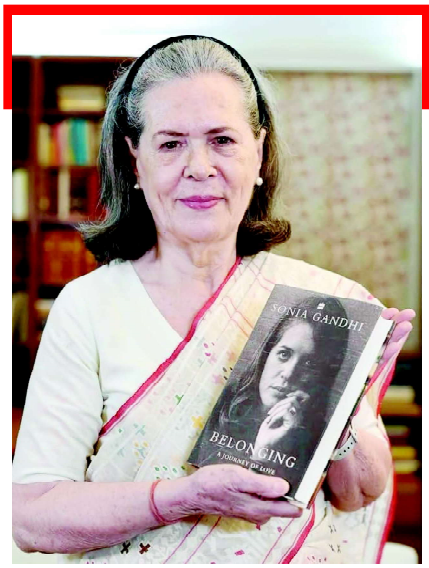
धनेश्वर चौधरी

महंगाई भेद नहीं करती

महंगाई जब बढ़ती है तो वह सरकारी और निजी कर्मचारी में भेद नहीं करती। प्याज, दाल, तेल, सब्जी और दवाइयों के दाम सबकी जेब से पैसा निकालते हैं। फिर राहत के मामले में यह भेदभाव क्यों? अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत पहुंच गई। भारतीय रिजर्व बैंक की छह प्रतिशत की ऊपरी सहन-सीमा भी टूट गई। प्याज 116 प्रतिशत से अधिक महंगा हुआ, लहसुन के दाम में 60 प्रतिशत से ज्यादा उछाल आया। ये आंकड़े नहीं, आम परिवारों के बिगड़ते घरेलू बजट की तस्वीर हैं।

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, पेंशनभोगियों को महंगाई राहत। लेकिन निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों, छोटे दुकानों और प्रतिष्ठानों के श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा दिहाड़ी कमाने वालों के हिस्से में क्या आता है? उनकी आमदनी **शेष पृष्ठ 2 पर**

सोनिया की कलम से खुले कांग्रेस के सियासी राज!



आत्मकथा ने फिर छेड़ी इतिहास सत्ता और जवाबदेही की बहस

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

सत्ता के गलियारों में दशकों तक प्रभाव रखने वाले गांधी परिवार की कहानी अब सोनिया गांधी की अपनी कलम से सामने है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की 544 पन्नों की आत्मकथा 'बिलॉनिंग : ए जर्नी ऑफ लव'(Belonging: A Journey of Love) के 10 नवंबर को प्रकाशित होते ही देश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। यह किताब केवल इटली से भारत पहुंची एक महिला की प्रेम कहानी, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत संघर्षों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसके पन्नों में भारतीय राजनीति के कई ऐसे अध्याय भी हैं, जिन पर आज तक सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने खड़े होते रहे हैं।

इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की राजनीतिक विरासत, बाबरी मस्जिद विध्वंस, 1975 का आपातकाल, 1984 के सिख विरोधी दंगे, 2004 में प्रधानमंत्री पद ठुकराने का फैसला और कांग्रेस के भीतर सत्ता के समीकरण-इन सभी विषयों पर सोनिया गांधी ने अपने अनुभव और दृष्टिकोण सामने रखे हैं। सवाल यह है कि क्या **शेष पृष्ठ 5 पर**

असम की मतदाता सूची में 2.19 लाख का इजाफा, 4.12 लाख नए नाम जुड़े

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

असम में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत नई मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी। इस सूची में कुल 2,51,76,910 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, जो 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित पिछली अंतिम मतदाता सूची से 2,18,771 अधिक हैं। इस बार 4,12,344 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जबकि 1,93,573 नाम हटाए गए। इस तरह नामों को जोड़ने और हटाने के बाद मतदाताओं की संख्या में करीब 2.19 लाख की शुद्ध वृद्धि हुई है।

आंकड़ों के लिहाज से यह केवल मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी नहीं है। इसके पीछे असम की विशिष्ट नागरिकता व्यवस्था, राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की लंबित **शेष पृष्ठ 3 पर**

असम में एसआईआर नहीं, है अलग व्यवस्था

असम में देश के दूसरे राज्यों की तरह विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर नहीं कराया गया। इसके स्थान पर पहले विशेष पुनरीक्षण (एसआर) और अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया अपनाई गई है।

इसके पीछे असम की अलग नागरिकता व्यवस्था और एनआरसी से जुड़ा संवेदनशील मामला है। नागरिकता अधिनियम के तहत असम के लिए विशेष प्रावधान हैं। नागरिकता से जुड़े मामलों की जांच सर्वोच्च न्यायालय **शेष पृष्ठ 3 पर**

11 दिसंबर तक जुड़वा सकते हैं नाम

मसौदा सूची जारी होने के साथ ही आम नागरिकों के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर भी शुरू हो गया है। निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इसके बाद 28 दिसंबर तक इनका निपटारा किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित करने का कार्यक्रम है।

जिन पात्र नागरिकों के नाम सूची में नहीं हैं, वे नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं।



छठ व्रतधारियों के लिए शुक्रेश्वर घाट पर पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी युवक समाज ने की विशेष व्यवस्था

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

गुवाहाटी में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी युवक समाज की ओर से इस वर्ष भी चार दिवसीय छठ महोत्सव-2026 का आयोजन किया जा रहा है। समाज के तत्वावधान में यह धार्मिक आयोजन शुक्रेश्वर घाट से लेकर फैंसी बाजार स्थित महावीर पार्क तक किया जाएगा।

समाज की ओर से जारी सूचना के अनुसार, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तथा अस्थायी स्नानगृह की समुचित व्यवस्था की गई है। आयोजकों ने छठव्रतियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से पर्व को श्रद्धा, सादगी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है।

समाज ने विशेष रूप से श्रद्धालुओं से घाटों पर डीजे एवं निजी साउंड सिस्टम का प्रयोग नहीं करने तथा पटाखे नहीं जलाने का आग्रह किया है। साथ ही अभिभावकों से बच्चों को अकेले नहीं छोड़ने और अपने वाहनों को निर्धारित स्थानों पर ही खड़ा करने की अपील की गई है। घाटों पर कोई संदिग्ध या लावारिस वस्तु दिखाई देने पर तत्काल वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों को सूचना देने को कहा गया है।

पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी युवक समाज के अध्यक्ष बृज किशोर सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह, महासचिव अनिल चौधरी, उप-सचिव राजेश शर्मा (पप्पू) तथा संयोजक विराज सिंह सहित अन्य पदाधिकारी आयोजन की तैयारियों में जुटे हैं।

पश्चिम चाराली तालाब परिसर में उमड़ेगा आस्था का सैलाब



जन जन विचार
...✍ वेददीप उपाध्याय
बिश्वनाथ चारिआली

बिश्वनाथ जिले के पश्चिम चाराली में इस वर्ष भी छठ महापर्व धूमधाम और व्यापक स्तर पर मनाने की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पूजा के सफल आयोजन और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पश्चिम चाराली छठ पूजा समिति ने फलफली पुखुरीजान तालाब परिसर में अपने अस्थायी कार्यालय का उद्घाटन किया।

बिश्वनाथ चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष बिक्रम दुबे ने फीता काटकर कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

सभा को संबोधित करते हुए बिक्रम दुबे ने कहा कि छठ पूजा केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, अनुशासन और स्वच्छता का भी प्रतीक है। उन्होंने विश्वास जताया कि अस्थायी कार्यालय के संचालन से पूजा की तैयारियों और आयोजन संबंधी कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने में समिति को मदद मिलेगी।

समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि फलफली तालाब के तट पर छठ पूजा को भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारियां जारी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पेयजल, रोशनी, बैठने की व्यवस्था और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

युवा भारतीय संघ ने की छठ घाटों पर सुंदर व्यवस्था

गुवाहाटी। लोकआस्था और सूर्योपासना के महापर्व छठ पूजा को लेकर युवा भारतीय संघ की ओर से फैंसी बाजार फेरी घाट, लाचित घाट एवं फेरी घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं।

संघ के महासचिव सूरज तिवारी ने बताया कि छठ महापर्व के दौरान घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने की तैयारी है, ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित वातावरण बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। संघ ने आयोजन को सफल बनाने के लिए पूजा समिति, प्रशासनिक व्यवस्था, घाट व्यवस्थापन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। संघ ने श्रद्धालुओं से परिवार सहित इस धार्मिक आयोजन में भाग लेकर पुण्य के भागी बनने की अपील की है।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

महंगाई भेद नहीं करती

भी क्या महंगाई के अनुपात में बढ़ती है? निजी क्षेत्र का कर्मचारी जब बढ़ती कीमतों के कारण अपने खर्च घटाता है, तब उसकी सुनवाई कौन करता है?

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता कोई अनुचित सुविधा नहीं, बल्कि आय को महंगाई के असर से बचाने का उपाय है। असली सवाल यह है कि ऐसी सुरक्षा बाकी कामगारों के लिए क्यों नहीं? क्या देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले करोड़ों निजी और असंगठित श्रमिकों की क्रयशक्ति बचाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है?

समाधान स्पष्ट है। न्यूनतम मजदूरी को महंगाई सूचकांक से नियमित रूप से जोड़कर संशोधित किया जाए। निजी क्षेत्र में समयबद्ध वेतन समीक्षा को प्रोत्साहन और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रभावी ढांचा बनाया जाए। खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर सख्ती, आपूर्ति व्यवस्था में सुधार और गरीब परिवारों को लक्षित राहत भी सुनिश्चित हो।

सरकार को यह समझना होगा कि महंगाई का बिल हर नागरिक चुकाता है, लेकिन उससे बचाव का अधिकार भी हर नागरिक को मिलना चाहिए। आखिर निजी कर्मचारी और मजदूर इस देश के नागरिक नहीं हैं क्या?

राशिफल

13 से 19 नवंबर, 2026 ।। विक्रम संवत 2083-**मास** : कार्तिक, **पक्ष** : शुक्ल, **तिथि** : चतुर्थी

मेष : इस सप्ताह आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृषभ : यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रह सकता है। नौकरी और कारोबार में सफलता मिलने के संकेत हैं। पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। खानपान पर ध्यान दें।

मिथुन : इस सप्ताह कामकाज में सुधार होगा। नौकरी और व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। तनाव से दूर रहें।

कर्क : इस सप्ताह काम का दबाव बढ़ सकता है। नौकरी में धैर्य से काम लें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

सिंह : यह सप्ताह आपके लिए उत्साह से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में सम्मान बढ़ेगा। गुस्से और जल्दबाजी से बचें।

कन्या : इस सप्ताह अधूरे काम पूरे करने का मौका मिलेगा। नौकरी में सावधानी से काम करें। पैसों के मामले में बजट बनाकर चलें। परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय संयम रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला : यह सप्ताह नई शुरुआत के लिए अच्छा हो सकता है। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। परिवार में खुशियां रहेंगी।

वृश्चिक : इस सप्ताह आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में सोच-समझकर निर्णय लें। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें।

धनु : इस सप्ताह भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी और कारोबार में सफलता के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रह सकता है। परिवार के साथ यात्रा की योजना बन सकती है। अपनी सेहत का ध्यान रखें।

मकर : इस सप्ताह मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार के बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें।

कुंभ : इस सप्ताह कामकाज में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अचानक खर्च बढ़ने की संभावना है। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें।

मीन : यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रह सकता है। नौकरी और कारोबार में प्रगति के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। योग और व्यायाम के लिए समय निकालें।

सप्ताह के पर्व/त्योहार

13 नवंबर (शुक्रवार) : वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत, नहान-खान के साथ श्री सूर्य षष्ठी व्रत प्रारंभ
14 नवंबर (शनिवार) : खरना, बाल दिवस
15 नवंबर (रविवार) : श्री सूर्य षष्ठी व्रत संध्या अर्घ्य
16 नवंबर (सोमवार) : श्री सूर्य षष्ठी व्रत प्रात: कालीन अर्घ्य
17 नवंबर (मंगलवार) : गोपाष्टमी
18 नवंबर (बुधवार) : अक्षय नवमी

●ज्योतिर्विद् आचार्य अखिलेश्वर शुक्ल
भाग्योदय : पहला तल्ला, सेंट्रल प्लाजा, एमएस रोड
फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781001 मो.-94350 40387

धन दिशा



साल के आखिरी महीनों में यह पांच काम जरूर निपटाएं

नवंबर शुरू हो गया है। दिवाली जा चुकी है और साल खत्म होने में बस दो महीने बचे हैं। यह वक्त थोड़ा रुककर अपनी वित्तीय तस्वीर देखने का है। मार्च में हड़बड़ी में टैक्स बचाने की कोशिश करने से बेहतर है कि अभी से तैयारी शुरू करें। पांच काम हैं, जो आज के बाद टालने नहीं हैं।

पहला काम: 80सी निवेश जांचें। सेक्शन 80सी में 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। पीपीएफ, ईएलएसएस, एलआईसी प्रीमियम, ईपीएफ, एसएसवाई-इनमें से क्या-क्या हो चुका है? अगर अभी भी जगह बाकी है तो ईएलएसएस में एसआईपी शुरू करें- ईएलएसएस में सबसे कम लॉक-इन (3 साल) और लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छे रिटर्न की संभावना है।

दूसरा काम: स्वास्थ्य बीमा की समीक्षा। क्या आपका स्वास्थ्य बीमा कवर परिवार की वर्तमान जरूरत के हिसाब से पर्याप्त है? अगर कवर 3-5 साल पहले लिया था और परिवार बड़ा हुआ है या माता-पिता को जोड़ना है, तो टॉप-अप या सुपर टॉप-अप प्लान लें। यह बहुत सस्ते में अतिरिक्त कवरेज देता है।

तीसरा काम: नॉमिनी अपडेट करें। बैंक खाता, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, एलआईसी पॉलिसी, ईपीएफ-इन सभी में नॉमिनी है या नहीं? और जो नॉमिनी है, क्या वह अभी भी सही है? शादी, बच्चे का जन्म, या किसी का निधन - इन घटनाओं के बाद नॉमिनी बदलना जरूरी हो जाता है। यह काम 10 मिनट में होता है, लेकिन इसका असर परिवार की पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है।

चौथा काम: पोर्टफोलियो की समीक्षा। साल में कम से कम एक बार अपने सभी निवेशों की समीक्षा करें। क्या एसआईपी सही फंड में जा रही है? क्या कोई फंड लगातार 2-3 साल से बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रहा है? क्या इक्वीटी-डेब्ट का अनुपात आपकी उम्र और जोखिम के हिसाब से सही है? यह समीक्षा खुद से या किसी भरोसेमंद एमएफडी या फाइनांसियल प्लानर के साथ करें।

पांचवां काम : आपातकालीन फंड जांचें। अगर आपका इमरजेंसी फंड 6 महीने के खर्च से कम हो गया है-जैसे त्योहारों में खर्च हुआ या कोई अचानक जरूरत पड़ी- तो इसे पहले भरें। इमरजेंसी फंड लिक्विड होना चाहिए- लिक्विड म्यूच्युअल फंड या उच्च आय वाले बचत खाते में रखें।

साल का अंत सिर्फ 31 दिसंबर मनाने का नहीं, बल्कि अगले साल की तैयारी का भी होता है। यह पांच काम अगर आज कर लिए तो जनवरी में नए साल की शुरुआत सच में अच्छी होगी।

अगले हफ्ते : नए साल में नई शुरुआत- एक सरल वित्तीय योजना कैसे बनाएं जो पूरे साल टिके।

इस कॉलम के लिए आपका कोई सवाल है? हमें भेजिए

-कोमल जैन

पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, संस्थापक, वेल्थप्लायर्स- मो. 9004510577

ब्रह्मपुत्र के तट पर गूंजेगा छठी मैया का जयकारा

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी



लोक आस्था, पवित्रता, त्याग और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अनुपम पर्व छठ पूजा एक बार फिर गुवाहाटी में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का वातावरण बनाने जा रहा है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा यह महापर्व अब असम की राजधानी गुवाहाटी की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का भी अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ब्रह्मपुत्र के तट पर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन व्रत का शुभारंभ शुक्रवार, 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ हो गया है। शनिवार, 14 नवंबर को खरना होगा। रविवार, 15 नवंबर को व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे, जबकि सोमवार, 16 नवंबर की सुबह उदीयमान सूर्य को दूसरा अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन होगा।

गुवाहाटी में छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, पारिवारिक समर्पण और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक बन चुकी है। इस अवसर पर विभिन्न समुदायों के लोग भी छठ घाटों पर पहुंचकर पर्व की खुशियों में सहभागी बनते हैं।

उगते और डूबते सूर्य की उपासना का अनूठा विधान

छठ पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें केवल उगते सूर्य ही नहीं, बल्कि अस्ताचलगामी सूर्य को भी समान श्रद्धा के साथ अर्घ्य दिया जाता है। यह परंपरा मनुष्य को जीवन के हर पड़ाव का सम्मान करने और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का संदेश देती है।

ब्रह्मपुत्र के घाटों पर उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़

गुवाहाटी में उमानंद क्षेत्र के निकट उजान बाजार, कचहरी, फैंसी बाजार और भरलुमुख सहित ब्रह्मपुत्र के विभिन्न तटों पर छठ पूजा की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इसके अलावा पांडु, मालीगांव, सूनचाली, बिरुबाड़ी, ज्योतिकुची, नारंगी और अन्य इलाकों में भी श्रद्धालु इस पर्व को मनाते हैं।

रविवार की शाम घाटों पर श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ जुटने की संभावना है। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सजकर पूजा सामग्री के साथ घाट पहुंचेंगी। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान दीपों की रोशनी, पारंपरिक छठ गीत और सामूहिक प्रार्थना ब्रह्मपुत्र के तट को एक अद्भुत आध्यात्मिक दृश्य में बदल देंगे।

आस्था के साथ सुरक्षा और स्वच्छता भी जरूरी

छठ पूजा के दौरान घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए सुरक्षा, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और यातायात प्रबंधन विशेष महत्व रखते हैं। पिछले वर्षों में प्रशासन ने प्रमुख घाटों पर बैरिकेडिंग, पुलिस निगरानी तथा आपदा प्रबंधन दलों की तैनाती जैसी व्यवस्थाएं की थीं। इस वर्ष की व्यवस्थाओं के संबंध में प्रशासन की आधिकारिक सूचना पर नजर रखना जरूरी होगा।

सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है छठ महापर्व

छठ पूजा की खूबसूरती इसकी धार्मिक आस्था के साथ-साथ सामाजिक समरसता में भी छिपी है। यह पर्व जाति, भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ता है। गुवाहाटी जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक महानगर में इसका व्यापक स्वरूप असम की समावेशी सामाजिक संस्कृति को भी मजबूती देता है। बिहार और पूर्वांचल से आकर असम को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले हजारों परिवारों के लिए छठ अपनी मिट्टी, परंपरा और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का अवसर भी है। वहीं स्थानीय लोगों की सहभागिता इस उत्सव को और व्यापक बनाती है।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

असम की मतदाता सूची में ...

प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई अलग पुनरीक्षण पद्धति भी महत्वपूर्ण है। देश के कई अन्य राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए मतदाता सूची की जांच की जा रही है, लेकिन असम में अलग प्रक्रिया अपनाई गई है। ऐसे में नई सूची के साथ यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है कि असम में एसआईआर क्यों नहीं हुआ और इस बार मतदाता सूची तैयार करने का तरीका क्या रहा?

महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, नई मसौदा सूची में 1,25,87,650 पुरुष और 1,25,88,939 महिला मतदाता शामिल हैं। तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या 321 है। इस प्रकार महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 1,289 अधिक है। 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में कुल 2,49,58,139 मतदाता थे। इसके बाद लगातार अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान 4.12 लाख से अधिक नए नाम शामिल किए गए और करीब 1.94 लाख नाम हटाए गए। दोनों आंकड़ों के अंतर से मतदाताओं की संख्या में 2,18,771 की वृद्धि हुई। नई सूची में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 2,87,233 युवा मतदाता भी शामिल हैं। इसके अलावा 2,05,962 दिव्यांग मतदाता और 85 वर्ष से अधिक उम्र के 1,22,198 मतदाता दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि मतदाता सूची में युवा और वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।

असम में एसआईआर नहीं...

की निगरानी में चल रही एनआरसी प्रक्रिया से भी जुड़ी है। एनआरसी का अंतिम प्रकाशन वर्ष 2019 में हुआ था, लेकिन इसे लेकर आगे की वैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहले स्पष्ट किया था कि असम में नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधानों और एनआरसी की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए यहां अलग तरीके से मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। एसआईआर में मौजूदा मतदाताओं को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी पात्रता साबित करने के लिए गणना प्रपत्र और आवश्यक दस्तावेज देने होते हैं। इसके विपरीत एसएसआर में पहले से दर्ज मतदाताओं के नाम मसौदा सूची में बने रहते हैं। नए पात्र मतदाताओं को शामिल करने और मृत, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टियों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाने पर जोर दिया जाता है।

संपादकीय

भीम-मीम गठबंधन

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाकर नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना इस गठबंधन की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मोर्चा वास्तव में सत्ता परिवर्तन का विकल्प बनेगा या विपक्षी वोटों के बिखराव का नया कारण?

मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश लोकतांत्रिक राजनीति में अस्वाभाविक नहीं है। इन समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और सत्ता में भागीदारी मांगने का पूरा अधिकार है। लंबे समय से मुख्यधारा की पार्टियों पर इन वर्गों को केवल चुनावी गणित के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में नया गठबंधन उनके भीतर नई राजनीतिक उम्मीद जगा सकता है।

हालांकि, इसकी राह आसान नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा था। केवल सामाजिक समीकरणों के आधार पर सत्ता तक पहुंचना संभव नहीं। संगठन, विश्वसनीय नेतृत्व, स्पष्ट नीतियां और जमीनी जनसमर्थन भी जरूरी हैं।

इस गठबंधन की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती विपक्षी एकता पर पड़ने वाला असर है। यदि यह समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के परंपरागत मतदाताओं में सेंध लगाता है, तो भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। लेकिन हर नए राजनीतिक विकल्प को भाजपा की बी-टीम बताकर खारिज करना भी लोकतांत्रिक दृष्टि से उचित नहीं।

लोकतंत्र में नए मोर्चों का स्वागत होना चाहिए, लेकिन उनकी असली परीक्षा नारों से नहीं, नीतियों, जनहित और चुनावी परिणामों से होगी। भीम-मीम गठबंधन सामाजिक न्याय की आवाज बनेगा या सत्ता की लड़ाई में एक और राजनीतिक समीकरण, इसका फैसला जनता करेगी।

आरएसी : आधी सीट के बदले पूरा किराया क्यों?

भारतीय रेलवे में आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन) व्यवस्था पर पुनर्विचार की खबर यात्रियों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। दशकों पुरानी इस व्यवस्था के तहत दो यात्रियों को एक ही बर्थ पर आधी-आधी जगह देकर यात्रा की अनुमति दी जाती है। सवाल है कि जब यात्री पूरा किराया चुकाता है, तो उसे पूरी सीट का अधिकार क्यों नहीं मिलता? विशेषकर लंबी दूरी की यात्रा में आधी सीट पर बैठना और सोना किसी यातना से कम नहीं। बुजुर्गों, महिलाओं और बीमार यात्रियों के लिए यह परेशानी और गंभीर हो जाती है। त्योहारों के मौसम में जब ट्रेनों में भारी भीड़ होती है, तब आरएसी मजबूरी का विकल्प बन जाता है। रेलवे का उद्देश्य अधिक यात्रियों को यात्रा का अवसर देना है, लेकिन सुविधा के नाम पर असुविधा को स्थायी व्यवस्था नहीं बनाया जा सकता। यदि रेलवे आरएसी समाप्त करने या इसमें सुधार करने पर विचार कर रहा है, तो यह स्वागतयोग्य कदम होगा।

भारत में घट रही है गरीबी

जन जन विचार
...✍ *प्रह्लाद सबनानी*

हाल ही में विश्व बैंक ने एक प्रतिवेदन जारी कर बताया है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों की संख्या तेजी से घट रही है। केंद्र सरकार की आर्थिक सलाहकार समिति की सदस्य श्रीमती शमिका रवि ने भी अपने एक रिसर्च पेपर में बताया है कि भारत में 10 वर्ष पूर्व तक गरीबी आंकलन के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाता था। इन सिफारिशों के अनुसार भारतीय नागरिकों को पूर्व निर्धारित स्तर तक कैलोरी प्राप्त करने हेतु होने वाले खर्च से यदि अधिक आय है तो उसे गरीबी की रेखा से ऊपर मान लिया जाता था। कैलोरी की आवश्यकता शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में निवासरत नागरिकों के लिए अलग अलग स्तर पर तय की जाती थी, इसे खाद्य गरीबी की संज्ञा भी दी जाती थी। इसके बाद, रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर गरीबी का आंकलन किया जाने लगा, जिसमें खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य, कपड़ा, मकान, शिक्षा आदि को जोड़ा गया है। भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या, देश की कुल जनसंख्या का, 29.5 प्रतिशत थी जो वर्ष 2023-24 में घटकर 3.9 प्रतिशत रह गई है। यह एक अतुलनीय उपलब्धि मानी जा रही है। पूरे भारत वर्ष में ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में कमी दृष्टिगोचर हुई है। विश्व बैंक के ही एक अन्य अनुमान के अनुसार, भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या, (अर्थात 3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की आय वाले नागरिक) वर्ष 2011 में 27 प्रतिशत थी जो वर्ष 2023 में घटकर 2.6 प्रतिशत हो गई है। जबकि, 4.2 अमेरिकी डॉलर तक की प्रतिदिन आय वाले नागरिकों की संख्या वर्ष 2011 के 57.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023 में 16.1 प्रतिशत रह गई है, जिसके वर्ष 2026 में 14.2 प्रतिशत एवं वर्ष 2028 में 12.1 प्रतिशत तक नीचे रहने का अनुमान विश्व बैंक द्वारा लगाया गया है।

भारत में निवासरत समस्त वर्गों, अल्पसंख्यकों सहित, के नागरिकों की गरीबी में कमी दिखाई दी है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में निवासरत अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों की गरीबी तेजी से घटी है। लगभग12 वर्ष पूर्व तक जनजातीय क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों के बीच गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या 50 प्रतिशत तक थी जो अब घटकर 12 प्रतिशत के स्तर तक नीचे आ गई है।

एक प्रश्न पूछा जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में यदि इतनी कमी आई है तो फिर गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के 85 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा भी गरीब वर्ग की सहायता के लिए विशेष योजनाएं क्यों चलाई जा रही है। इस प्रश्न के उत्तर में यह तर्क दिया जा रहा है कि उक्त योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्ग को सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इससे गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री पर कम खर्च करना पड़ रहा है और इस मद से हुई बचत को गरीब वर्ग अपने सामाजिक स्तर में सुधार पर खर्च करने लगा है। भारत में हाल ही के समय में गरीब वर्ग की खाद्य सामग्री में फल, दूध, पनीर, दूध से बने अन्य पदार्थ, अंडे, आदि भी शामिल हो गए हैं। इससे गरीब वर्ग के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार दृष्टिगोचर हुआ है। इसके साथ ही, पूर्व में केंद्र सरकार को भारी मात्रा में अन्न का स्टॉक रखना पड़ता था। अन्न के स्टॉक को, बहुत बड़ी मात्रा में, चूहे नुक्सान पहुंचाते थे एवं वर्षा ऋतु में भी अन्न का भारी मात्रा में नुकसान होता था। अब, चूंकि गेहूं एवं चावल जैसी खाद्य सामग्री को गरीब जनता के बीच सहायता के रूप में बांट दिया जाता है, इससे देश में अन्न की बचत ही हो रही है। केंद्र सरकार के अन्न को स्टोर करने की मद पर भी खर्च बहुत कम हो गया है। आज भारत में गरीब वर्ग भी गेहूं एवं चावल के स्थान पर पोषण सामग्री का अधिक उपयोग कर रहा है। 12 वर्ष पूर्व, भारत में 63 प्रतिशत नागरिकों द्वारा ताजे फलों का सेवन किया जाता था, आज यह संख्या बढ़कर 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है। देश में दालों एवं फलों जैसी खाद्य सामग्री का उपयोग लगातार बढ़ रहा है।

देश में बेरोजगारी की दर में भी भारी कमी दृष्टिगोचर हुई है। भारत में बेरोजगारी की दर अब घटकर 3.1 प्रतिशत तक नीचे आ गई है। परंतु, विभिन्न राज्यों के बीच बेरोजगारी की दर में भारी अंतर दिखाई दे रहा है। गुजरात में बेरोजगारी की दर केवल 0.9 प्रतिशत है तो छतीसगढ़ में केवल 1.9 प्रतिशत है। परंतु केरल में 12 प्रतिशत है तो हिमाचल प्रदेश में 17 प्रतिशत है। इतना बड़ा अंतर, राज्यों द्वारा निर्धारित की जा रही व्यापार की नीतियों में अंतर के चलते दिखाई दे रहा है। जिस प्रदेश की व्यापार एवं उद्योगों की नीतियां, व्यापारियों एवं उद्योगों के अधिक हित में हैं, उन प्रदेशों में रोजगार के अधिक अवसर निर्मित हो रहे हैं। आज भारत का युवा वर्ग अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में अधिक समय व्यतीत करने लगा है इसके कारण 18 से 30 वर्षों की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है जबकि 30 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों में बेरोजगारी की दर बहुत कम है। 30 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही युवाओं को आभास होने लगता है कि अब तो जो भी रोजगार मिले उसे प्राप्त करना ही बेहतर है। इसी प्रकार, लगभग 10वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण करने वाले युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर बहुत कम है परंतु स्नातक एवं स्नात्तकोतर तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है। क्योंकि, अधिक पढ़ा लिखा वर्ग सरकारी नौकरी ढूंढने में अपना अधिक समय बर्बाद कर देता है। जबकि कम पढ़ा लिखा युवा सरकारी नौकरी के चक्कर से अपने आप को दूर रखते हुए जो भी रोजगार के अवसर उसे प्राप्त होता है उसे स्वीकार कर लेता है।

केरल, पंजाब एवं गोवा राज्यों में रोजगार के अधिक अवसर निर्मित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन प्रदेशों में सरकारी नीतियां ही इसके लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। जबकि, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में रोजगार के पर्याप्त अवसर निर्मित हो रहे हैं क्योंकि इन प्रदेशों में वातावरण व्यापार एवं उद्योगों के लिए सहायक है। उक्त कारणों के चलते ही भारत का पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग, उत्तरी एवं पूर्वी भाग की तुलना में अधिक तेजी से विकास कर रहा है। भारत की कुल जनसंख्या में से लगभग 60 प्रतिशत नागरिक ही श्रम के रूप में अपनी भागीदारी प्रदान कर रहे हैं जबकि वियतनाम में 70 प्रतिशत, बांग्लादेश में 67 प्रतिशत है। अर्थात, जितने अधिक नागरिकों को रोजगार उपलब्ध होगा देश के आर्थिक विकास में नागरिकों की भागीदारी उतनी अधिक होगी। हर्ष का विषय है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की श्रम में भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

भारत में वर्ष 2011 से वर्ष 2023 के बीच 49.6 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सका है एवं रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं यथा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जल जीवन मिशन, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, आदि के सफल क्रियान्वयन से यह संभव हो सका है।

सपना दिखाकर वोट लेने वाले मुगालते में न रहें : सम्राट

जन जन विचार
...✍ वरुण कुमार, पटना

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जनता को नया सपना दिखाकर वोट हासिल करने की चाहत रखने वाले मुगालते में न रहें। बिहार की जनता काफी जागरूक है और वह सब कुछ समझती है। जो लोग केवल नए-नए सपने दिखाकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं, उन्हें जनता मंच से उतारना भी अच्छी तरह जानती है।

मुख्यमंत्री गुरुवार को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने नए लाभुकों के बीच राशन कार्ड और नई जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के लिए लाइसेंस का वितरण किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक सफलताओं का जिक्र करते हुए उनकी जीत का फार्मूला भी साझा किया। उन्होंने कहा, 'लोग अक्सर पूछते हैं कि मोदी और नीतीश के जीतने का फार्मूला क्या है?



इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब है- जो गरीबों के लिए काम करेगा, गरीब उसी को अपना वोट देगा।'

उन्होंने कहा कि विपक्ष को लगता है कि नए सपने दिखाकर जनता का वोट हासिल किया जा सकता है, लेकिन बिहार के मतदाता जागरूक हैं। वे काम और वादों के बीच का अंतर अच्छी तरह समझते हैं।

मुख्यमंत्री ने नेताओं को धरातल पर रहकर काम करने की नसीहत देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वे जनता से ज्यादा होशियार हैं। वास्तविकता यह है कि नेता जनता के प्रतिनिधि और उसके प्रतिबिंब मात्र हैं।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

सोनिया की कलम से...

यह आत्मकथा इतिहास के कुछ अनकहे पहलुओं पर रोशनी डालेगी या गांधी परिवार के राजनीतिक फैसलों का एक पक्षीय बचाव बनकर रह जाएगी? यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा है।

प्रधानमंत्री पद ठुकराया या सत्ता का दूसरा रास्ता चुना?

आत्मकथा का सबसे दिलचस्प और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद की घटनाओं से जुड़ा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत के बाद सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन उन्होंने इस पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया।

सोनिया के मुताबिक, प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने अपने बेटे राहुल और बेटी प्रियंका से भी चर्चा की थी। दोनों इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं के बाद परिवार की सुरक्षा को लेकर उनके मन में गहरी आशंका थी। उन्होंने अपने फैसले को अंतरात्मा की आवाज बताया।

लेकिन भारतीय राजनीति में यह सवाल आज भी प्रासंगिक है कि प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बावजूद क्या सोनिया गांधी सत्ता के केंद्र से दूर थीं? यूपीए सरकार के दस वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। सरकार और पार्टी के बीच वास्तविक शक्ति-संतुलन क्या था, यह बहस आज भी समाप्त नहीं हुई है। आत्मकथा इस विवाद को फिर जीवित कर सकती है।

बाबरी विध्वंस : एक घटना जिसने बदल दी राजनीति की दिशा

6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस भारतीय राजनीति का ऐसा मोड़ बना, जिसने देश के सामाजिक और राजनीतिक विमर्श को गहराई से प्रभावित किया। सोनिया गांधी ने इस घटना को लेकर अपनी पीड़ा और प्रतिक्रिया का उल्लेख किया है। उनके लिए यह केवल एक धार्मिक ढांचे का गिरना नहीं, बल्कि देश की धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी पहचान के सामने खड़ी हुई गंभीर चुनौती थी।

इस प्रसंग के जरिए उन्होंने भाजपा और आरएसएस की राजनीति पर अपनी आलोचनात्मक दृष्टि भी रखी है। हालांकि, बाबरी विवाद का इतिहास केवल एक घटना तक सीमित नहीं है। इसमें दशकों का राजनीतिक संघर्ष, न्यायिक प्रक्रिया, विभिन्न सरकारों की भूमिका और देश की सामाजिक एकता से जुड़े गंभीर सवाल शामिल हैं।

सोनिया की आत्मकथा इस पुराने विवाद को एक बार फिर राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला सकती है।

आपातकाल और 1984 के दंगे : कांग्रेस की विरासत पर असहज सवाल

आत्मकथा का सबसे संवेदनशील पक्ष कांग्रेस और गांधी परिवार के अपने इतिहास से जुड़ा है। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को लेकर सोनिया ने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों, इंदिरा गांधी के अलगाव और उनके आसपास बनते दबावों का उल्लेख किया है।

लेकिन लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल को केवल राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर नहीं परखा जा सकता। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां और नागरिक अधिकारों का हनन ऐसे तथ्य हैं, जिनकी जवाबदेही आज भी लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या परिस्थितियों का वर्णन उन गलतियों की जिम्मेदारी को भी स्वीकार करता है?

इसी तरह 1984 के सिख विरोधी दंगों को सोनिया गांधी ने दुखद और शर्मनाक अध्याय बताया है। उन्होंने हिंसा रोकने में प्रशासनिक विफलता और पीड़ितों को न्याय मिलने में हुई देरी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही राजीव गांधी पर लगाए गए आरोपों के संदर्भ में उनका पक्ष भी सामने रखा है।

लेकिन हजारों लोगों की जान लेने वाली उस हिंसा के मामले में केवल दुख और संवेदना पर्याप्त नहीं हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यही वह बिंदु है जहां पाठक आत्मकथा में प्रस्तुत पक्ष और ऐतिहासिक तथ्यों के बीच अंतर को समझना चाहेंगे।

राजीव गांधी की हत्या : निजी त्रासदी से राष्ट्रीय राजनीति तक

सोनिया गांधी की जिंदगी में राजनीति का प्रवेश किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि लगातार हुई पारिवारिक त्रासदियों से जुड़ा रहा। पुस्तक में 1965 में कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से मुलाकात, प्रेम, विवाह और भारत आने के बाद के जीवन का विस्तार से वर्णन है।

राजीव गांधी राजनीति से दूर रहकर विमान चालक के रूप में अपना जीवन बिताना चाहते थे। लेकिन संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद परिस्थितियां बदल गईं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और बाद में 1991 में उनकी भी हत्या कर दी गई।

सोनिया ने इन घटनाओं के व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रभावों को सामने रखा है। उन्होंने यह भी बताया है कि किस तरह इन घटनाओं ने उन्हें सार्वजनिक जीवन में आने के लिए मजबूर किया। इस दृष्टि से पुस्तक गांधी परिवार की सत्ता-कथा के पीछे छिपे निजी दर्द को भी सामने लाती है।

भाजपा का हमला, कांग्रेस का बचाव

पुस्तक प्रकाशित होते ही भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस और गांधी परिवार से जुड़े विवादित ऐतिहासिक घटनाक्रमों को अपने पक्ष में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। भाजपा प्रवक्ता सी.आर. केसवन ने विशेष रूप से आपातकाल और 1984 के सिख विरोधी दंगों का उल्लेख करते हुए पुस्तक की व्याख्याओं पर सवाल उठाए हैं।

वहीं कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की आलोचना को राजनीतिक हमला बताते हुए कहा है कि सोनिया गांधी को अपने जीवन और अनुभवों को प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है। उनके अनुसार, निजी संस्मरणों को राजनीतिक विवाद का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए।

लेकिन लोकतंत्र में किसी भी सार्वजनिक जीवन से जुड़े बड़े नेता की आत्मकथा केवल निजी दस्तावेज नहीं रह जाती। जब उसमें राष्ट्रीय इतिहास, सत्ता के फैसलों और विवादित घटनाओं का उल्लेख होता है, तो उसकी सार्वजनिक समीक्षा स्वाभाविक है।

प्रकाशन विवाद ने भी खड़े किए सवाल

पुस्तक के प्रकाशन से पहले प्रकाशक बदलने का विवाद भी चर्चा में रहा। पहले पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के साथ प्रकाशन की योजना थी, लेकिन संपादकीय बदलावों को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। बाद में हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने पुस्तक प्रकाशित की।

सोनिया गांधी ने प्रकाशन से जुड़े घटनाक्रम को सरकार की आलोचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यापक सवालों से जोड़कर देखा है। दूसरी ओर, पेंगुइन ने इस मामले में अपनी ओर से राजनीतिक दबाव के आरोपों को सही नहीं माना और कहा कि प्रकाशन संबंधी असहमति को अलग संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

इस पूरे घटनाक्रम ने लेखकीय स्वतंत्रता, प्रकाशकों की संपादकीय भूमिका और राजनीतिक रूप से संवेदनशील पुस्तकों के प्रकाशन पर नई बहस छेड़ दी है।

गांधी परिवार की विरासत का नया राजनीतिक अध्याय

सोनिया गांधी की यह आत्मकथा ऐसे समय आई है, जब कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटी है और राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी की नई राजनीतिक पीढ़ी के प्रमुख चेहरे हैं। ऐसे में पुस्तक को केवल अतीत की यादों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता।

यह पुस्तक गांधी परिवार की विरासत का पक्ष प्रस्तुत करती है, लेकिन इसके साथ कई ऐसे सवाल भी खड़े करती है, जिनका उत्तर केवल संस्मरणों से नहीं मिल सकता। आपातकाल की जिम्मेदारी, 1984 के दंगों का न्याय, बाबरी विध्वंस के समय राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका और यूपीए सरकार के दौरान सत्ता का वास्तविक केंद्र-ये सभी विषय स्वतंत्र ऐतिहासिक और राजनीतिक पड़ताल की मांग करते हैं।

आखिरकार, सोनिया गांधी की आत्मकथा का महत्व इस बात में नहीं है कि उसमें गांधी परिवार की कितनी निजी कहानियां सामने आई हैं, बल्कि इस बात में है कि वह भारतीय राजनीति के पुराने सवालों को कितनी ईमानदारी से छूती है। आत्मकथा लेखक का अपना सच हो सकती है, लेकिन वह इतिहास का अंतिम सच नहीं होती। गांधी परिवार को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, तो देश के नागरिकों को उस पक्ष की पड़ताल करने का भी पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में इतिहास किसी एक परिवार, दल या नेता की निजी संपत्ति नहीं होता।

पटना 'स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी' पुरस्कार से सम्मानित

जन जन विचार
...✍ वरुण कुमार, पटना



स्वच्छता के क्षेत्र में पटना नगर निगम ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नई दिल्ली में बुधवार को आयोजित 10वें स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के पुरस्कार समारोह में पटना को 'स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से यह पुरस्कार प्रदान किया। इस उपलब्धि से बिहार की राजधानी ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान स्थापित की है।

समारोह में नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, पटना की महापौर सीता साहू, उप महापौर रेशमी कुमारी, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव संदीप पुडकलकट्टी और नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने पुरस्कार ग्रहण किया।

इस समारोह की खास बात यह रही कि पटना नगर निगम की टीम अपने दो सफाईकर्मियों अमरजीत मांझी (नूतन राजधानी अंचल) और रॉकी पासवान (अजीमाबाद अंचल) को भी साथ लेकर पहुंची। दोनों सफाईकर्मियों ने भी टीम के साथ यह सम्मान प्राप्त किया। यह पहल शहर को स्वच्छ बनाने में दिन-रात जुटे सफाईकर्मियों के योगदान और समर्पण को सम्मान देने का प्रतीक बनी।

बेहतर कचरा प्रबंधन और जनभागीदारी से मिली सफलता

पटना नगर निगम को यह उपलब्धि डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था में सुधार, पुराने कचरे (लीगेसी वेस्ट) के नियमानुसार निस्तारण, जन शिकायतों के त्वरित समाधान और ठोस कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के प्रयासों के आधार पर मिली है। इसके साथ ही स्वच्छता अभियान में आम नागरिकों की बढ़ती भागीदारी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महापौर सीता साहू ने इस सम्मान को पूरे पटना शहर और नागरिकों को समर्पित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पटना नगर निगम की पूरी टीम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार के शहरों में विकास और स्वच्छता को नई गति मिल रही है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सफाईकर्मियों, निगमकर्मियों और पटनावासियों को बधाई दी।

उप महापौर रेशमी कुमारी ने कहा कि यह सम्मान सफाईकर्मियों की कड़ी मेहनत और नागरिकों के सहयोग का परिणाम है। स्वच्छ शहर का निर्माण केवल नगर निगम के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। यह पुरस्कार स्वच्छता के संकल्प को और मजबूती से आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा।

वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट से मजबूत होगी व्यवस्था

नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा कि आने वाले समय में पटना क्लस्टर में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना, पुराने कचरे का पूर्ण निस्तारण और इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने की योजना है। इसके अलावा नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करने और मोबाइल कोर्ट जैसी पहल भी की जाएगी। इन योजनाओं से शहर की स्वच्छता और कचरा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

लगातार बेहतर हुआ पटना का प्रदर्शन

पटना नगर निगम ने पिछले तीन स्वच्छ सर्वेक्षणों में लगातार अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। वर्ष 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में पटना ने बिहार में पहला स्थान हासिल किया था। उस दौरान नगर निगम को वाटर प्लस सर्टिफिकेट और 1-स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग भी मिली थी।

वर्ष 2024 में पटना ने 3-स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग हासिल करने के साथ 'प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर' पुरस्कार भी प्राप्त किया। वहीं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में 'स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी' का सम्मान हासिल कर पटना ने अपनी उपलब्धियों की कड़ी को आगे बढ़ाया है।

इस सम्मान ने एक बार फिर साबित किया है कि किसी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में प्रशासनिक प्रयासों के साथ सफाईकर्मियों की मेहनत और आम नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

पवित्रता और नियम-संयम के साथ करें भगवान सूर्य की उपासना

जन जन विचार
...✍ वरुण कुमार, पटना

पं. कमलापति त्रिपाठी प्रमोद



दीपावली के बाद अब देशभर में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित यह महापर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन अनुष्ठान में व्रती पूरी निष्ठा, पवित्रता और नियम-संयम के साथ भगवान सूर्य की उपासना करते हैं।

आध्यात्मिक गुरु पंडित कमलापति त्रिपाठी के अनुसार, छठ महापर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति, सूर्य और जल के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी पर्व है। इसमें डूबते और उगते सूर्य दोनों को अर्घ्य देने की विशेष परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि छठी मैया की विधिवत आराधना करने से संतान की खुशहाली, परिवार की सुख-शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

13 नवंबर को नहाय-खाय से होगी शुरुआत

पंडित कमलापति त्रिपाठी के अनुसार, वर्ष 2026 में छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर, शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ होगी। इस दिन व्रती स्नान कर घर और रसोई की साफ-सफाई करते हैं। इसके बाद शुद्धता के साथ सात्विक भोजन तैयार कर ग्रहण किया जाता है। आमतौर पर कद्दू-भात और चने की दाल इस दिन के पारंपरिक भोजन में शामिल होते हैं।

14 नवंबर को लोहंडा और खरना

महापर्व के दूसरे दिन 14 नवंबर, शनिवार को खरना मनाया जाएगा। इसे लोहंडा भी कहा जाता है। इस दिन व्रती दिनभर उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद गुड़ की खीर, रोटी सहित पारंपरिक प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना के बाद व्रती लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करते हैं, जिसका समापन उषा अर्घ्य के बाद पारण से होता है।

15 नवंबर को संध्या अर्घ्य

छठ महापर्व का तीसरा दिन 15 नवंबर, रविवार को होगा। इस दिन व्रती और श्रद्धालु छठ घाटों पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। पंडित कमलापति त्रिपाठी के अनुसार, इस वर्ष संध्या अर्घ्य का संभावित समय शाम 5 बजकर 28 मिनट है। इस दौरान सूप में ठेकुआ, फल, नारियल और अन्य पूजन सामग्री सजाकर भगवान सूर्य को अर्पित की जाएगी।

16 नवंबर को उषा अर्घ्य के साथ होगा समापन

महापर्व के अंतिम दिन 16 नवंबर, सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सूर्योदय का संभावित समय सुबह 6 बजकर 44 मिनट बताया गया है। अर्घ्य देने के बाद व्रती छठी मैया की पूजा-अर्चना करेंगे और परिवार की सुख-समृद्धि एवं संतान के मंगलमय जीवन की कामना करेंगे। इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाएगा।

आस्था, अनुशासन और प्रकृति की उपासना का पर्व

आध्यात्मिक गुरु पंडित कमलापति त्रिपाठी ने बताया कि छठ महापर्व में स्वच्छता, पवित्रता, संयम और अनुशासन का विशेष महत्व है। यह पर्व समाज में एकता, समरसता और सामूहिक सहयोग का संदेश भी देता है। जाति, वर्ग और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर सभी लोग एक साथ घाटों पर भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। यही छठ महापर्व की सबसे बड़ी विशेषता है।

क्रिकेट के अगले चार साल का खाका तैयार

वर्ष 2032 से 2035 के बीच होंगे छह बड़े आईसीसी टूर्नामेंट

जन जन विचार
...✍ स्पोर्ट्स डेस्क

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर आईसीसी ने अगले चार वर्षों का संभावित कार्यक्रम सामने रख दिया है। वर्ष 2032 से 2035 के बीच क्रिकेट प्रेमियों को छह बड़े वैश्विक टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे। इस प्रस्तावित कार्यक्रम की शुरुआत 2032 में टी-20 विश्व कप से होगी, जबकि 2035 में वनडे विश्व कप के साथ इस चक्र का समापन होगा। खास बात यह है कि 2033 और 2035 दोनों वर्षों में दो-दो बड़े आईसीसी आयोजन प्रस्तावित हैं।

आईसीसी के इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के व्यस्त कैलेंडर को व्यवस्थित करना और सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के आयोजन के लिए बेहतर समय उपलब्ध कराना है। हालांकि, फिलहाल यह संभावित कार्यक्रम है और अंतिम कैलेंडर को लेकर प्रक्रिया जारी है।

अगले चार वर्षों में टी-20, एकदिवसीय और टेस्ट क्रिकेट के तीनों प्रारूपों को वैश्विक मंच पर पर्याप्त स्थान देने की योजना बनाई गई है। इससे क्रिकेट के अलग-अलग प्रारूपों के प्रशंसकों को लगातार बड़े मुकाबले देखने का अवसर मिलेगा।



2033 में दो बड़े टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी के प्रारूप पर सवाल

वर्ष 2033 क्रिकेट के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वर्ष जून में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और अक्टूबर में चैंपियंस ट्रॉफी प्रस्तावित है। हालांकि, चैंपियंस ट्रॉफी किस प्रारूप में आयोजित होगी, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आठ टीमों के टूर्नामेंट की योजना जरूर शामिल है, लेकिन मेजबान देश को लेकर भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

2034 में जुलाई में टी-20 विश्व कप

वर्ष 2034 में टी-20 विश्व कप के आयोजन के लिए जुलाई का महीना प्रस्तावित किया गया है। यह समय इंग्लैंड के घरेलू क्रिकेट सत्र के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, टूर्नामेंट के आयोजन स्थल की घोषणा अभी नहीं की गई है।

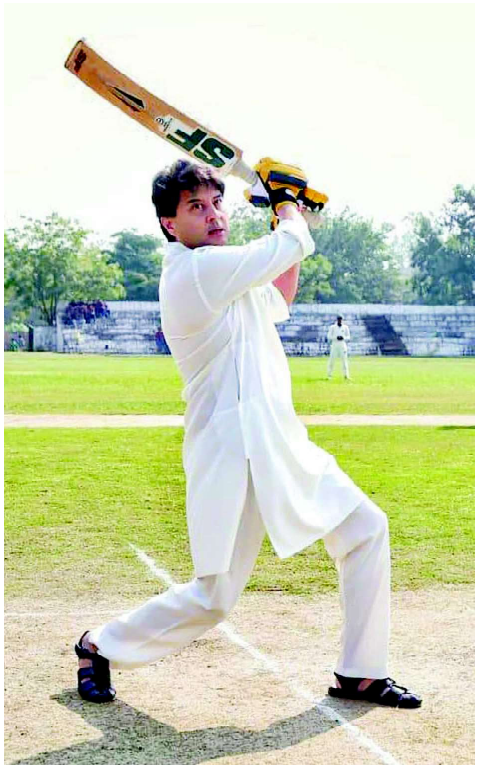
2035 में वनडे विश्व कप और टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल

वर्ष 2035 में क्रिकेट प्रशंसकों को दो बड़े आयोजनों का रोमांच देखने को मिल सकता है। इस वर्ष वनडे विश्व कप के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी प्रस्तावित है। हालांकि, दोनों प्रतियोगिताओं की तारीखों और मेजबानी को लेकर अभी अंतिम कार्यक्रम सामने नहीं आया है।

फ्रेंचाइजी लीग और राजस्व बंटवारे पर भी नजर

आईसीसी की बैठकों में केवल अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीगों के नियमन पर भी चर्चा प्रस्तावित है। इसके लिए गठित समीक्षा समूह की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। इस समूह का नेतृत्व बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल कर रहे हैं। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया भी इसके सदस्य हैं। इसके अलावा सदस्य देशों के बीच राजस्व के बंटवारे का मुद्दा भी बैठक के एजेंडे में शामिल है। मौजूदा चक्र के लिए लगभग 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के राजस्व वितरण को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई गई है।

कुल मिलाकर, आईसीसी का प्रस्तावित 2032-35 कैलेंडर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों को संतुलित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, फ्रेंचाइजी लीगों के बढ़ते प्रभाव और द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के दबाव के बीच आईसीसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वैश्विक क्रिकेट कैलेंडर में संतुलन बनाए रखने की होगी।



मध्य प्रदेश के शिवपुरी में क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन अवसर पर बल्ले से शॉट लगाते केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया।

अंडर-19 एशिया कप : खिताब के लिए भारत-पाकिस्तान में होगी जंग

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता एक बार फिर रोमांच की नई कहानी लिखने को तैयार है। एसीसी पुरुष अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में शनिवार, 14 नवंबर को भारत और पाकिस्तान की युवा टीमें खिताब के लिए आमने-सामने होंगी। इस मुकाबले में केवल एशिया कप की ट्रॉफी दांव पर नहीं होगी, बल्कि पिछली हार का हिसाब चुकता करने का दबाव भी भारतीय टीम पर रहेगा।

भारत ने गुरुवार को खेले गए सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को आठ विकेट से करारी शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरी ओर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया। अब दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच होने वाली भिड़ंत पर क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टिकी हैं।

भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला खास चुनौती लेकर आया है। ग्रुप चरण में पाकिस्तान के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष एशिया कप के फाइनल में भी पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। ऐसे में भारतीय युवा खिलाड़ियों के सामने इस बार पिछली नाकामियों को पीछे छोड़कर खिताब अपने नाम करने की चुनौती होगी।

आर्यवीर सहवाग बन सकते हैं भारत के तुरुप का इक्का

इस खिताबी मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग पर विशेष निगाहें रहेंगी। टूर्नामेंट में उनका बल्ला लगातार रन उगल रहा है। आर्यवीर अब तक चार मुकाबलों में 303 रन बना चुके हैं, जिसमें एक शानदार शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप चरण के मुकाबले में वह बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे थे। फाइनल में उनके पास अपनी प्रतिभा साबित करने और भारतीय टीम को खिताब दिलाने का सुनहरा मौका होगा। आर्यवीर के अलावा कप्तान लक्ष्य रायचंदानी और अन्य युवा बल्लेबाजों से भी बड़ी पारियों की उम्मीद रहेगी।

कप्तान लक्ष्य के सामने खिताब दिलाने की चुनौती

कप्तान लक्ष्य रायचंदानी की अगुवाई में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में शानदार खेल दिखाया। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत में लक्ष्य ने 93 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। इससे भारतीय बल्लेबाजी की मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब फाइनल में कप्तान की रणनीति, बल्लेबाजों का धैर्य और गेंदबाजों की सटीकता भारत की सफलता तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।

कब और कहां देख सकेंगे मैच

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल शनिवार, 14 नवंबर को ओमान के अल अमीरात क्रिकेट मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय दर्शकों के लिए मुकाबला सुबह 10.30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस सुबह 10 बजे होगा।

छठ व्रत : तपस्या, त्याग व अटूट आस्था का महापर्व

जन जन विचार
...✍ धर्म डेस्क

छठ महापर्व भारतीय लोकसंस्कृति का ऐसा अनुपम पर्व है, जिसमें आस्था केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि नदियों, तालाबों और प्रकृति की गोद में साकार होती है। सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना को समर्पित यह पर्व श्रद्धा, संयम, पवित्रता, त्याग और आत्मानुशासन का अद्भुत संगम है। चार दिनों तक चलने वाला यह कठिन व्रत जितना धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतना ही सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी विशिष्ट है।

बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से निकलकर छठ महापर्व आज देश के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ विदेशों में भी व्यापक रूप से मनाया जाने लगा है। असम की राजधानी गुवाहाटी में भी ब्रह्मपुत्र के तट पर छठ पूजा की छटा देखते ही बनती है। हजारों परिवार इस पर्व के माध्यम से अपनी परंपरा, संस्कृति और लोकविश्वास से जुड़े रहते हैं।

चार दिनों की कठिन साधना

छठ व्रत की शुरुआत नहाय-खाय से होती है। इस दिन व्रती स्नान कर घर और रसोई की विशेष साफ-सफाई करते हैं तथा शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। लौकी की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल जैसे पारंपरिक व्यंजनों का विशेष महत्व है। भोजन बनाने से लेकर ग्रहण करने तक शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है।

दूसरे दिन खरना का विधान होता है। व्रती दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को पूजा-अर्चना करते हैं और गुड़ की खीर, रोटी तथा फल का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ हो जाता है। इस दौरान व्रती अन्न और जल दोनों का त्याग कर पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ पूजा करते हैं।

तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है। बांस के सूप और दउरा में फल, नारियल, गन्ना, ठेकुआ और अन्य पूजन सामग्री सजाकर श्रद्धालु नदी, तालाब या निर्धारित घाटों पर पहुंचते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को जल और दूध से अर्घ्य अर्पित किया जाता है। छठ के पारंपरिक गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है।

चौथे और अंतिम दिन उषा अर्घ्य का विधान है। सूर्योदय से पहले ही व्रती और श्रद्धालु घाटों पर पहुंच जाते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इसी के साथ चार दिनों की कठिन साधना पूर्ण होती है।

डूबते सूर्य की पूजा का अनूठा संदेश

छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अस्त होते और उदय होते, दोनों सूर्य की आराधना की जाती है। सामान्यत: संसार उगते सूर्य को प्रणाम करता है, लेकिन छठ का विधान डूबते सूर्य को भी उतनी ही श्रद्धा से नमन करना सिखाता है।

इसके पीछे जीवन का एक गहरा दर्शन छिपा है। जीवन में सफलता और उन्नति के साथ-साथ संघर्ष, अवसान और कठिन परिस्थितियों का भी सम्मान होना चाहिए। यह पर्व संदेश देता है कि हर अवस्था का अपना महत्व है और प्रकृति का प्रत्येक रूप पूजनीय है। सूर्य ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का आधार हैं। पृथ्वी पर जीव-जगत का अस्तित्व सूर्य की ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। इसीलिए छठ पर्व को प्रकृति के प्रति मनुष्य की कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी माना जाता है।

ठेकुआ की मिठास और लोकगीतों की मधुरता

छठ की पहचान इसके पारंपरिक प्रसाद और लोकगीतों से भी है। गेहूं के आटे, गुड़ और घी से तैयार ठेकुआ इस पर्व का सबसे लोकप्रिय प्रसाद है। इसके अलावा केला, नारियल, सेब, संतरा, गन्ना और मौसमी फलों का विशेष महत्व होता है।

छठ के गीतों में मां की ममता, संतान की मंगलकामना, परिवार की खुशहाली और लोकजीवन की भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। 'केलवा जे फरेला घवद से' और 'कांच ही बांस के बहंगिया' जैसे पारंपरिक गीत पीढ़ियों से इस महापर्व की सांस्कृतिक पहचान बने हुए हैं।

इन गीतों में केवल धार्मिक भावना ही नहीं, बल्कि लोकसमाज की स्मृतियां, पारिवारिक रिश्ते और जीवन के सुख-दुख भी समाहित हैं।

महिलाओं की साधना और पारिवारिक समर्पण

छठ व्रत में महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। माताएं और बहनें परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना के साथ यह कठिन व्रत करती हैं। हालांकि पुरुष भी पूरी श्रद्धा के साथ छठ व्रत रखते हैं।

इस पर्व में परिवार का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी रूप में सहभागी बनता है। कोई प्रसाद तैयार करता है, कोई पूजा सामग्री जुटाता है तो कोई घाट की व्यवस्था में सहयोग करता है। इस प्रकार छठ केवल व्रती का व्यक्तिगत धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह जाता, बल्कि पूरे परिवार और समाज का सामूहिक उत्सव बन जाता है।

प्रकृति संरक्षण का भी देता है संदेश

छठ महापर्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ाव है। पूजा में बांस के सूप, मिट्टी के दीपक, प्राकृतिक फल और पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। नदी, तालाब और जलाशय इस पर्व के प्रमुख पूजा स्थल होते हैं।

यह परंपरा हमें जलस्रोतों की स्वच्छता और प्रकृति के संरक्षण का महत्व समझाती है। लेकिन विडंबना यह है कि जिन नदियों और तालाबों को हम पूजा के लिए पवित्र मानते हैं, उन्हीं में कई बार पूजा के बाद प्लास्टिक और अन्य कचरा छोड़ दिया जाता है। इसलिए छठ की सच्ची भावना तभी पूरी होगी, जब श्रद्धालु पूजा के साथ-साथ घाटों और जलस्रोतों की स्वच्छता का भी संकल्प लें।

36 घंटे का निर्जला उपवास, डूबते और उगते सूर्य की आराधना; लोकपरंपरा में छिपा है प्रकृति संरक्षण, पारिवारिक सुख और सामाजिक समरसता का संदेश



छठी मैया की महिमा

कांच के सूप में सजाए फलवा,
दीप जलाए घाट किनार।
आ जइहें छठी मैया हमार,
पूरा करिहें सबके अरमान॥
डूबत सूरज के अर्घ्य चढ़ाईं,
भक्ति के दीप जलाईं।
सुख-समृद्धि और खुशहाली खातिर,
मैया से अरजी लगाईं॥
उगिहें सूरज देव भिनुसार,
गूंजे जय-जयकार।
छठी मैया के महिमा न्यारी,
महके घर-आंगन संसार॥

छठी मैया आ जइहें अंगना हमार

छठी मैया आ जइहें अंगना हमार,
सज गइल घाट, सज गइल संसार।
हाथ में सूपवा, मन में विश्वास,
पूरा करिहें मैया सबके आस॥
केरवा के पात, नारियल के थार,
दीपक से चमके घाट हजार।
गंगा जल से अरघ सजवनी,
सूरज देव के जोत जगवनी॥
उग हे सूरज देव, भइल भिनुसार,
तोहरे किरिन से चमके संसार।
लाल चुनरिया, माथे सिंदूर,
मैया रखिहें सबके भरपूर॥
सुख मिले परिवार, खुश रहे संसार,
बनल रहे सबके प्रेम अपार।
बारंबार करेली विनती हमार,
छठी मैया राखिहें लाज हमार॥

छठी मैया के दरबार सजल बा

छठी मैया के दरबार सजल बा,
घाटे-घाटे दीप जरल बा।
फूलवा, फलवा, नारियल के थार,
लेके अइनीं मैया तोहार दुआर॥



हे छठी मैया, अरज सुन लऽ हमार,
सुख-शांति बरसइहऽ अंगना हमार।
तोहरे भरोसे बा दुनिया हमार,
करिहऽ मैया सबके बेड़ा पार॥
केरवा के डाली, गन्ना के भार,
सूपवा में सजल बा फल हजार।
निर्जल रहि के व्रतिया पुकारे,
दर्शन दीं मैया, कष्ट निवारे॥
डूबत सूरज के अर्घ चढ़ाईं,
भक्ति के ज्योति मन में जगाईं।
भोर भइल, पूरब में लाली,
उगिहऽ सूरज देव, छठी मैया निराली॥
लाल चुनरिया, माथे सिंदूर,
मैया के महिमा बा जग में मशहूर।
हँसत रहे घर-परिवार हमार,
बनल रहे मैया तोहार दुलार॥



ৰাইজৰ কথা ৰাইজৰ মাজলৈ

সাপ্তাহিক

জন জন বিচাৰ



Guwahati, 13 November, 2026 Friday :: শুক্রবাৰ, কাতি, শুক্লপক্ষ, চতুর্দশী, শকাব্দ ১৯৪৮

মণিপুৰত পুনৰ ৰক্তাক্ত সংঘর্ষ, গুলীত নিহত কুকি মহিলা

জন জন বিচাৰ
...ইম্ফল

মণিপুৰত পুনৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাজ্যখনৰ কাংপকপি জিলাত বৃহস্পতিবাৰে দুটা প্রতিদ্বন্দ্বী উগ্রপন্থী গোটৰ মাজত হোৱা গুলীবর্ষণত এগৰাকী কুকি মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন দুজন লোক আহত হয়। এই ঘটনাক কেন্দ্র কৰি অঞ্চলটোত নতুনকৈ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাৰ প্রতিবাদত কুকি সংগঠনে জিলাখনত ৪৮ ঘণ্টীয়া সম্পূর্ণ বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। লগতে অঞ্চলটোৰ পৰা সকলো নিৰাপত্তা বাহিনী প্রত্যাহাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সংগঠনটোৱে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্রায় ১১ বজাত কাংপকপি জিলাৰ তাফৌ কুকি গাঁও আৰু কাষৰীয়া সেনাপতি জিলাৰ কেলেংজাঙৰ সমীপত দুটা প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্রোহী গোটৰ মাজত গুলীয়াগুলী আৰম্ভ হয়। সেই সময়ত পথাৰত কাম কৰি থকা তাফৌ কুকি গাঁৱৰ কে. চংলোই নামৰ মহিলাগৰাকী গুলীবিদ্ধ হয় আৰু ঘটনাস্থলীতে তেওঁৰ মৃত্যু হয়। গুলীবর্ষণত এছ. ডেভিদ চংলোই আৰু লামখোচোন চংলোই নামৰ আন দুজন লোক আহত হয়। তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভর্তি কৰোৱা হৈছে।

ঘটনাৰ পিছতে কুকি সংগঠনে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন কৰিছে। নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সাধাৰণ নাগৰিকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাত ব্যর্থ হোৱা বুলি অভিযোগ কৰি সংগঠনটোৱে কাংপকপি জিলাৰ পৰা সকলো নিৰাপত্তা বাহিনী আঁতৰোৱাৰ দাবী জনাইছে। আনহাতে, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্রণৰ বাবে অঞ্চলটোত চিআৰপিএফ, বিএছএফ আৰু অসম ৰাইফলছৰ অতিৰিক্ত জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে। নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অভিযান চলোৱাৰ সময়ত স্থানীয় একাংশ লোকে, বিশেষকৈ মহিলাসকলে, বাহিনীক গাঁৱত প্রৱেশ কৰাত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰে।

উল্লেখযোগ্য যে এই অঞ্চলত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত আন এক ঘটনাক লৈও উত্তেজনা অব্যাহত আছে। যোৱা ২৮ অক্টোবৰত তাফৌ কুকি গাঁৱৰ দুজন যুবক নিৰুদ্দেশ হৈছিল আৰু ১ নৱেম্বৰত কাষৰীয়া সেনাপতি জিলাত তেওঁলোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। এই ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি কমিটী অন ট্রাইবেল ইউনিটি (চিঅটিইউ) নামৰ কুকি সংগঠনটোৱে ইতিমধ্যে প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে। সংগঠনটোৰ আন এটা দাবী হৈছে, তাফৌ কুকি গাঁওখনক সেনাপতি জিলাৰ পৰিৱর্তে কাংপকপি জিলা আৰক্ষীৰ অধীনত ৰখা। ৰাজ্য চৰকাৰে যুবক দুজনৰ হত্যাৰ তদন্ত ৰাষ্ট্রীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)ৰ হাতত অর্পণ কৰাৰ বিষয়টো বিবেচনা কৰি আছে।

ইফালে, উখৰুল জিলাৰ চিনাকেইথিৰ সমীপতো ধান চপাই থকা কৃষকৰ এটা দলৰ ওপৰত সন্দেহযুক্ত উগ্রপন্থীয়ে গুলীচালনা কৰে। এই ঘটনাত এজন লোক গুলীবিদ্ধ হয়। নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ প্রেৰণ কৰাৰ লগতে আন কৃষকসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ঘূৰাই অনাৰ উদ্যোগ চৰকাৰৰ

ইম্ফল। ৰাজ্যখনত পুনৰ হিংসাৰ ঘটনা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্রী য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙে সকলো জনগোষ্ঠীৰ প্রতিনিধিত্ব থকা এখন সমিতি গঠনৰ উদ্যোগ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। ইম্ফলস্থিত মুখ্যমন্ত্রীৰ সচিবালয়ত মণিপুৰৰ ১০টা জনজাতীয় জনগোষ্ঠীৰ প্রতিনিধিৰ সৈতে অনুষ্ঠিত বৈঠকত তেওঁ এই কথা প্রকাশ কৰে।

মুখ্যমন্ত্রীৰ মতে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত পাৰস্পৰিক বিশ্বাস, সহযোগিতা আৰু সম্প্রীতিৰ পৰি�ৰেশ গঢ়ি তোলাই হব এই সমিতিৰ মূল উদ্দেশ্য। শেহতীয়াকৈ নতুন দিল্লীত প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোদীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি সন্দর্ভত আলোচনা হৈছিল। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐক্য আৰু সংলাপৰ বাবে কোনো উমৈহতীয়া মঞ্চ আছে নেকি বুলি প্রধানমন্ত্রীয়ে জানিব বিচাৰিছিল। তাৰ পিছতে সকলো জনগোষ্ঠীক সামৰি এখন প্রতিনিধিত্বমূলক সমিতি গঠনৰ দিশত চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছে।

দীর্ঘদিনীয়া জনগোষ্ঠীয় সংঘাতৰ পিছত মণিপুৰত শান্তি আৰু স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই অনাৰ প্রচেষ্টা অব্যাহত থকাৰ সময়তে পুনৰ সংঘটিত হোৱা এই গুলীবর্ষণ আৰু বন্ধৰ আহ্বানে পৰিস্থিতিক অধিক জটিল কৰি তুলিছে। নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত আস্থা পুনৰ প্রতিষ্ঠা কৰাটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবে এতিয়া এক ডাঙৰ প্রত্যাহ্বান হৈ পৰিছে।

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা জাহ্নু বৰুৱাৰ পত্নী গায়ত্রী বৰুৱাৰ পুনেত আকস্মিক বিয়োগ

জন জন বিচাৰ
...নতুন দিল্লী

অসমীয়া চলচ্চিত্র জগতৰ বিশিষ্ট পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাৰ পত্নী গায়ত্রী বৰুৱাৰ বৃহস্পতিবাৰে পুনেত আকস্মিকভাৱে মৃত্যু ঘটে। ১২ নৱেম্বৰত পুনেৰ এখন ৰেস্তোৰাঁত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্রহণ কৰি থকা অৱস্থাতে হঠাৎ ঢলি পৰে গায়ত্রী। প্রাথমিকভাৱে তেওঁ হৃদ্‌ৰোগত আক্রান্ত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে যদিও মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্রতিবেদন প্রকাশ নোপোৱালৈকে মৃত্যুৰ প্রকৃত কাৰণ নিশ্চিত হোৱা নাই।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসৰি, ৰেস্তোৰাঁত আহাৰ গ্রহণ কৰি থকাৰ সময়তে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰাত তেওঁক ততাতৈয়াকৈ ওচৰৰ এখন চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয়। চিকিৎসকে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে।

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা জাহ্নু বৰুৱাৰ ভতিজা তথা পৰিচালক মঞ্জুল বৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে, গায়ত্রী বৰুৱা পুনেস্থিত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র আর্কাইভৰ কেণ্টিনত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। তাত তেওঁ অসমীয়া চলচ্চিত্র জগতৰ

ৰেস্তোৰাঁত আহাৰ গ্রহণ কৰি থকা অৱস্থাতে ঢলি পৰে গায়ত্রী, সম্ভাব্য হৃদ্‌ৰোগত আক্রান্ত হৈ মৃত্যু



কালজয়ী ছবি ‘হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খায়’ৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ কামত নিয়োজিত আছিল। দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্রহণ কৰি থকা সময়তে হঠাৎ ঢলি পৰাত তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসকৰ প্রচেষ্টা সফল নহল।

মঞ্জুল বৰুৱাই লগতে জানিবলৈ দিয়ে যে মৃত্যুৰ পূর্বে গায়ত্রী বৰুৱাৰ কোনো পৰিচিত অসুস্থতা, জ্বৰ বা আন শাৰীৰিক সমস্যাৰ লক্ষণ নাছিল। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতহে মৃত্যুৰ প্রকৃত কাৰণ স্পষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।

উল্লেখযোগ্য যে চলচ্চিত্রৰ প্রতি থকা একে অনুৰাগৰ সূত্রে জাহ্নু বৰুৱা আৰু গায়ত্রী বৰুৱাৰ মাজত পৰিচয় ঘটিছিল। ১৯৮৯ চনত দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল। গায়ত্রী নিজেও চলচ্চিত্র নির্মাণৰ সৈতে জড়িত আছিল আৰু জাহ্নু বৰুৱাৰ সৃষ্টিশীল যাত্রাত তেওঁ আছিল অন্যতম প্রেৰণাৰ উৎস।

জাহ্নু বৰুৱাৰ কেইবাখনো উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র নির্মাণৰ ক্ষেত্রত গায়ত্রীৰ প্রত্যক্ষ ভূমিকা আৰু উৎসাহৰ কথা বিশেষভাৱে চর্চিত। ৰাষ্ট্রীয় বঁটাপ্রাপ্ত ‘বান্ধোন’ চলচ্চিত্রখনৰ সৃষ্টিৰ আঁৰতো তেওঁৰ প্রেৰণা আছিল বুলি জানিব পৰা যায়। ২০০৮ চনৰ ২৬/১ৰ মুম্বাই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণৰ পটভূমিত চলচ্চিত্র নির্মাণৰ ক্ষেত্রতো বাজেটৰ সীমাবদ্ধতাৰ বাবে জাহ্নু বৰুৱাই প্রথমে দ্বিধাবোধ কৰিছিল। কিন্তু গায়ত্রীয়ে তেওঁক সীমিত বাজেটতে ছবিখন নির্মাণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল।

মৃত্যুৰ সময়ত গায়ত্রী বৰুৱাই স্বামী জাহ্নু বৰুৱা আৰু অভিনেতা পুত্র ওজু বৰুৱাক এৰি থৈ যায়। তেওঁৰ আকস্মিক বিয়োগে অসমীয়া চলচ্চিত্র জগতৰ লগতে সাংস্কৃতিক মহলত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পেলাইছে।

বাংলাদেশ সীমান্তত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া

জন জন বিচাৰ
...✍ গুৱাহাটী

মেঘালয়ৰ দক্ষিণ-পশ্চিম গাৰো পাহাৰ জিলাত ছয়জন বাংলাদেশী নাগৰিক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সীমান্ত পাৰ হৈ বাংলাদেশত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগত তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। একে সময়তে জিলাখনৰ স্বাস্থ্যসেৱা, শিক্ষা আৰু কৃষকৰ জীৱিকাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতো জিলা প্ৰশাসনে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে।

জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বিকাশ বৰ্মাই সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত জনোৱা অনুসৰি, জিকজাক অঞ্চলত চলোৱা এক আৰক্ষী অভিযানত মুঠ সাতজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। ইয়াৰে ছয়জন বাংলাদেশী নাগৰিক। তেওঁলোকে দিল্লী, বেংগালুৰু আৰু ছুৰাটকে ধৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত বসবাস কৰি থকাৰ পিছত মেঘালয়ৰ মাজেৰে বাংলাদেশত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে।

বাংলাদেশৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত আৰু অসমৰ সৈতে আন্তঃৰাজ্যিক সীমা থকা জিলাখনত সীমান্ত পাৰাপাৰ, অনুপ্ৰৱেশ আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহ ৰোধৰ বাবে আৰক্ষীয়ে নিৰীক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে। আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে অৱশ্যে জিলাখনত কোনো উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ বা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ পুনৰুত্থানৰ লক্ষণ নাই বুলি স্পষ্ট কৰে।

নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধেও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আহিছে। শেহতীয়া এটা অভিযানত এন ডি পি এছ আইনৰ অধীনত দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে ২,০০০টা যাবা টেবলেট জব্দ কৰা হয়। জিলাখন ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ প্ৰধান পথ নহয় যদিও সৰু পৰিসৰৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বেহাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে।

ইফালে, মহিলা আৰু শিশুৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ, বিশেষকৈ পকছ' আইনৰ অধীনত ৰুজু হোৱা গোচৰসমূহক লৈও আৰক্ষীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে। কিশোৰী গৰ্ভধাৰণ আৰু নাবালিকাৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতনৰ দৰে ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় আৰু বজাৰ অঞ্চলত সজাগতা অভিযান চলোৱা হৈছে।

জিলাখনৰ উপায়ুক্ত অনিন্দঞ্জয় ৰাজশ্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰীত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰা স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু কৃষকৰ জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সমস্যাসমূহ চিনাক্ত কৰি সমাধানৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে। মাতৃ আৰু শিশুৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰাৰ বাবে 'আৰ্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেণ্ট মিছন'ৰ অধীনত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিশেষকৈ ঘৰত প্ৰসৰ কৰাৰ প্ৰৱণতা আৰু মাতৃ-মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে।

উপায়ুক্তগৰাকীৰ মতে, কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাই ঘৰত থকা সন্তান আৰু পশুধনৰ যত্নৰ চিন্তাত চিকিৎসালয়লৈ যাবলৈ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে, নিশা জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিতো কিছুমানে ঘৰতেই প্ৰসৰ কৰায়। এই সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ মেলন, জিকজাক আৰু ছালমানপাৰা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহত সজাগতা অভিযান চলোৱা হৈছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু চিকিৎসালয়ত ২৪ ঘণ্টাই উপলব্ধ সেৱাৰ বিষয়েও মহিলাসকলক অৱগত কৰা হৈছে। দুৰ্গম বনাঞ্চলত ম'বাইল নেটৱৰ্কৰ দুৰ্বলতাই চিকিৎসা সেৱা লাভৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে।

শিক্ষাক্ষেত্ৰতো বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পুনৰ শিক্ষাৰ মূলসুঁতিলৈ ঘুৰাই অনাৰ বাবে বিশেষ জৰীপ চলোৱা হৈছে। বিশেষ পাঠদান, সাক্ষৰতা প্ৰমাণীকৰণ আৰু মুক্ত বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক শিক্ষাৰ সুযোগ দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত জিলাখনৰ তুলনামূলকভাৰে দুৰ্বল ফলাফলৰ কাৰণ বিশ্লেষণ কৰি বছৰৰ শেষৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিৰ অধীনত নিয়মীয়াকৈ খাদ্য যোগান আৰু সপ্তাহত অন্ততঃ এদিন কণী দিয়াটো নিদ্ৰিশ্চত কৰিবলৈও নিৰীক্ষণ চলিছে।



ধূপধলীয়া, জ্যোতিকুছিৰ ছট ঘাটত ছট পূজাৰ প্ৰস্তুতিৰ অংশ হিচাপে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা অভিযান চলোৱা হয়। অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে ঘাটটো পৰিষ্কাৰ কৰি ভক্তসকলৰ বাবে উপযোগী কৰি তোলা হৈছে।

ভূমি পট্টা, জনজাতিকৰণ আৰু মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীত নাজিৰাত আটছাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ

জন জন বিচাৰ
...✍ নয়নমণি ফুকন, নাজিৰা

ভূমিৰ অধিকাৰ, অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা আৰু ন্যায্য মজুৰিৰ দাবীত আজি নাজিৰাত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সস্থা (আটছু)। আটছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে নাজিৰা শাখাৰ উদ্যোগত ৰদ্ৰূপায়ণ কৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত দুই শতাধিক আটছুৰ কৰ্মী আৰু চাহ-শ্ৰমিক মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে।

অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ নাজিৰা শাখাৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণৰ পৰা উলিওৱা প্ৰতিবাদী সমদলটোৱে নাজিৰাৰ ৰাজপথ পৰিভ্ৰমণ কৰি সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত হয়। তাত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে।

চাহ জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আৰু প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আটছুই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী উত্থাপন কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক বংশানুক্ৰমিকভাৱে বসবাস কৰি অহা মাটিৰ স্থায়ী ভূমি পট্টা প্ৰদান, চাহ জনগোষ্ঠীক সংবিধান অনুসৰি অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান, পাঁনতম মজুৰি আইন, ১৯৪৮ৰ নীতি-নিৰ্দেশনা অনুসৰি দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি আৰু বন্ধ হৈ থকা চৰাইদেউ চাহ বাগিচা শীঘ্ৰে পুনৰ মুকলি কৰাৰ দাবী বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য।

প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ মতে, অসম তথা দেশৰ



অৰ্থনীতিলৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ অৱদান অপৰিসীম। অথচ যুগ যুগ ধৰি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি অহা এই জনগোষ্ঠীৰ বহু পৰিয়ালে আজিও ভূমিৰ অধিকাৰ, উপযুক্ত মজুৰি আৰু অন্যান্য মৌলিক সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। বন্ধ চৰাইদেউ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ জীৱন-জীৱিকাৰ অনিশ্চয়তাই পৰিস্থিতি অধিক জটিল কৰি তুলিছে।

প্ৰতিবাদৰ অন্তত আটছুৰ নাজিৰা শাখাৰ সভাপতি সঞ্জয় গোৱালা আৰু সম্পাদক ভূপেন ঘাটোৱাৰৰ স্বাক্ষৰিত এখন স্মাৰক-পত্ৰ নাজিৰা সমজিলাৰ আয়ুক্তৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। স্মাৰক-পত্ৰখনত উত্থাপিত দাবীসমূহৰ ওপৰত শীঘ্ৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব, সামাজিক-শৈক্ষিক বিকাশ আৰু সাংবিধানিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনোৱা হয়।

চাহ জনগোষ্ঠীৰ ন্যায্য অধিকাৰৰ দাবীত আটছুৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীয়ে পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যখনৰ চাহ শ্ৰমিক সমাজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাসমূহৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে।

এই সপ্তাহৰ ৰাশিফল

০৬ নৱেম্বৰ ২০২৬ৰ পৰা ১২ নৱেম্বৰ ২০২৬ লৈ

মেষ : মানসিক সুখ শান্তি বৃদ্ধি। কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ ফল লাভ। সামাজিক ক্ষেত্ৰত ব্যস্ততা বৃদ্ধি হব পাৰে।

বৃষ: চেষ্টাৰ সফলতা লাভ। ভাগ্যৰ সহায় থাকিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত সাবধানতা অৱলম্বন কৰিব।

মিথুন: ব্যাবসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা লাভ। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো শুভ। পিতৃৰ শৰীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন হব।

কৰ্কট: প্ৰতিযগিতামূলক কাৰ্যত কৃতকাৰঞ্জ্যতা লাভ। ব্যাবসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ। আকস্মিক কোনো ঘটনাই দুদ্ৰিশ্চন্তাত পেলাব পাৰে।

সিংহ: মানসিক উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। দৈনন্দিন কৰ্মব্যস্ততা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৰনা আছে। বাৰ্তা বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব।

কন্যা : মানসিক সুখ শান্তি বৃদ্ধি। সন্তানৰ পৰা মানসিক শান্তি লাভ। প্ৰতিযগিতামূলক কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকক।

তুলা: কৰ্মক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো শুভ। মানসিক সুখ শান্তি থাকিব। সন্তানৰ প্ৰতি সচেতন হব।

বৃশ্চিক: আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো শুভ। চেষ্টাৰ সাফল্য অৰ্জন। মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি হব পাৰে।

ধনু : শৰীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন হব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সন্মুখীন হব পাৰে। চেষ্টাত বাধাৰ সৃষ্টি হব পাৰে।

মকৰ: বাৰ্তা বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। মানসিক উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। ব্যাবসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ।

কুম্ভ : সামাজিক ক্ষেত্ৰত কৰ্মব্যস্ততা বৃদ্ধি। ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৰনা আছে। শৰীৰ স্বাষ্টৰ প্ৰতি সচেতন হব।

মীন: কৰ্মক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো শুভ। সামাজিক ক্ষেত্ৰত জৰিত কাৰ্যত শুনাম অৰ্জন। স্যাষ্টকৰ টোপনিৰ প্ৰটি মনোনিবেশ ৰাখিব।

- হিতেন শৰ্মা শাস্ত্ৰী
অধ্যাপক, বিশ্ব জ্যোতিষ বিদ্যাপীঠ, অসম শাখা
যোগাযোগ : ৯৮৫৪০২৬৭৭৯

ধেমাজিত ১০০ শতাংশ কৃষকৰ পঞ্জীয়নৰ লক্ষ্য

জন জন বিচাৰ
...✍ গুৱাহাটী

ধেমাজি জিলাৰ সকলো কৃষকক অহা ১৫ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত পঞ্জীয়নৰ আওতালৈ অনাৰ লক্ষ্য নির্ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষিমন্ত্রী পীযূষ হাজৰিকাই। জিলাখনত বর্তমানলৈ ৮৩ শতাংশ কৃষকৰ পঞ্জীয়ন সম্পূৰ্ণ হৈছে। বাকী থকা কৃষকসকলৰ পঞ্জীয়ন নির্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ তেওঁ বিভাগীয় বিষয়াসকলক কঠোৰ নির্দেশ দিছে। কৃষি আঁচনিৰ অগ্রগতি পর্যালোচনাৰ লগতে বিভিন্ন কৃষি প্রকল্প পৰিদর্শন কৰি মন্ত্রীগৰাকীয়ে কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি আৰু কৃষিক্ষেত্রৰ সম্ভাৱনা সম্প্রসাৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।

কেবিনেট মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগু, সাংসদ প্রদান বৰুৱা আৰু বিধায়ক ভুৰন পেগু তথা জীৰন গগৈৰ সৈতে ধেমাজি ভ্রমণ কৰা হাজৰিকাই প্রথমে অৰ্ণাই চাপৰিত



প্রগতিশীল কৃষক ভুৰন পেগুৰে ২২ বিঘা মাটিত গঢ়ি তোলা সমন্বিত কৃষি পাম পৰিদর্শন কৰে। এই পামত তামোল, বিলাহী, অমিতা আৰু মাটিকঁঠালৰ খেতিৰ লগতে পলিটেংক পদ্ধতিৰে মাছ পালন কৰা হৈছে।

ইয়াৰ পিছতে তেওঁ ডিমৌৰ শণ খেতি প্রকল্প পৰিদর্শন কৰি ইয়াৰ বাণিজ্যিক সম্ভাৱনা সম্পর্কে বুজ লয়। দীপা অঞ্চলত শ্রী বামুন ইছলাৰী আৰু দিলীপ বড়োৰ তেলপাম আৰু বহুফচলীয়া উদ্যান শস্যৰ পামো পৰিদর্শন কৰে মন্ত্রীগৰাকীয়ে। এই সময়ছোৱাত কৃষকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা আৰু সমস্যাৰ বিষয়েও বুজ লয়।

পৰৱর্তী সময়ত জিলা আয়ুক্তৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পর্যালোচনা বৈঠকত কৃষকৰ পঞ্জীয়নৰ কাম ১৫ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নির্দেশ দিয়ে। লগতে অধিকসংখ্যক কৃষক উৎপাদক কোম্পানী (এফ পি চি) গঠনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বিষয়াসকলক কয়, যাতে কৃষকসকলে সামূহিকভাৱে খেতি কৰাৰ লগতে বজাৰ লাভৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে।

মন্ত্রীগৰাকীয়ে পথাৰতে নিয়মীয়াকৈ 'খেতি বচাওক' বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি শস্যৰ সমস্যা সমাধানৰ নির্দেশ দিয়াৰ লগতে তেলপাম খেতিৰ উপযোগী ভূমি চিনাক্ত কৰিবলৈ কয়। জিলাখনত মখানা খেতিৰ সম্ভাৱনা অন্বেষণৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰো পৰামর্শ দিয়ে। কৃষি আন্তঃগাঁথনি পুঁজিৰ অধীনত সাহায্য লাভ কৰোঁতে স্থানীয় উদ্যোগীসকলে সম্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবেও তেওঁ বিষয়াসকলক নির্দেশ দিয়ে। কৃষিক্ষেত্রত শস্যৰ বৈচিত্র্যকৰণ, কৃষকৰ পঞ্জীয়ন আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ জৰিয়তে ধেমাজিৰ কৃষি অর্থনীতিক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়।

অৰুণাচলৰ অৰণ্যত নতুন ফুলৰ প্রজাতিৰ সন্ধান

জন জন বিচাৰ
...✍ ইটানগৰ

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্রাকৃতিক সম্পদ আৰু জৈৱ-বৈচিত্র্যৰ সমৃদ্ধ ভাণ্ডাৰত সংযোজিত হ'ল আন এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। অৰুণাচল প্রদেশৰ চাংলাং জিলাৰ বিজয়নগৰ অঞ্চলত গৱেষকসকলে আৰিষ্কাৰ কৰিছে এবিধ নতুন ফুলৰ উদ্ভিদ প্রজাতি। 'ডিছপৰপছিছ ক্রিছপাটা' নামৰ এই উদ্ভিদবিধৰ আৰিষ্কাৰ কেৱল অৰুণাচলৰ বাবেই নহয়, ভাৰতৰ উদ্ভিদ-বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ ক্ষেত্রতো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোজন। কিয়নো ভাৰতত এই প্রথমবাৰৰ বাবে 'ডিছপৰপছিছ' গণৰ কোনো উদ্ভিদৰ উপস্থিতি নথিভুক্ত কৰা হৈছে।

গৱেষকসকলে বিজয়নগৰ অঞ্চলৰ সমুদ্রপৃষ্ঠৰ পৰা প্রায় ২,৫০০ৰ পৰা ২,৮০০ মিটাৰ উচ্চতাত এই উদ্ভিদবিধৰ সন্ধান লাভ কৰে। এই আৰিষ্কাৰৰ তথ্য আন্তঃৰাষ্ট্রীয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিষয়ক গৱেষণা পত্রিকা Phytotaxaত প্রকাশ পাইছে। উদ্ভিদবিধৰ বৈশিষ্ট্য, ইয়াৰ প্রাকৃতিক বাসস্থান আৰু উদ্ভিদজগতত ইয়াৰ স্থান সম্পর্কে গৱেষণামূলক তথ্য প্রকাশ পোৱাটোৱে এই আৰিষ্কাৰক অধিক তাৎপর্যপূৰ্ণ কৰি তুলিছে।

অৰুণাচল প্রদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্রী চৌনা মেইনে বৃহস্পতিবাৰে সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'যোগে এই আৰিষ্কাৰৰ কথা ৰাজহুৱা কৰে। তেওঁ কয় যে এই নতুন উদ্ভিদৰ সন্ধানে ৰাজ্যখনৰ চহকী জৈৱ-বৈচিত্র্য আৰু বনাঞ্চলৰ



পৰিৱেশতন্ত্রৰ গুৰুত্ব পুনৰ উন্মোচন কৰিছে। এই সফলতাৰ বাবে গৱেষকসকলৰ লগতে আৰিষ্কাৰৰ ক্ষেত্রত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা স্থানীয় লোকসকললকো তেওঁ অভিনন্দন জনায়। লগতে ৰাজ্যখনৰ বনাঞ্চল আৰু ইয়াৰ অন্যান্য উদ্ভিদ তথা প্রাণীকুল সংৰক্ষণৰ প্রয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।

উত্তৰ-পূৰৰ অৰণ্য: উদ্ভিদ-বৈচিত্র্যৰ অমূল্য ভাণ্ডাৰ

ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যৰ বাবেই নহয়, উদ্ভিদ আৰু প্রাণীৰ বিচিত্র সমাহাৰৰ বাবেও বিশেষভাৱে পৰিচিত। পাহাৰ, উপত্যকা, ঘন অৰণ্য, নদী আৰু বিভিন্ন উচ্চতাৰ জলবায়ুগত পৰিৱেশে এই অঞ্চলত অসংখ্য উদ্ভিদ প্রজাতিৰ বিকাশৰ অনুকূল পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে। অৰুণাচল প্রদেশৰ দৰে ৰাজ্যত এতিয়াও বহু অচিনাকি উদ্ভিদ আৰু জীৱৰ সন্ধান লাভৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি এনে আৰিষ্কাৰে ইংগিত দিয়ে।

বিজয়নগৰৰ দৰে দুর্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলত ২,৫০০ৰ পৰা ২,৮০০ মিটাৰ উচ্চতাত এই উদ্ভিদৰ সন্ধান পোৱাটোৱে পর্বতীয়া পৰিৱেশতন্ত্রৰ বৈচিত্র্যৰ প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিছে। এনে অঞ্চলৰ বিশেষ জলবায়ু, মাটিৰ গুণাগুণ আৰু বনাঞ্চলৰ পৰিৱেশে কিছুমান নির্দিষ্ট উদ্ভিদৰ বাবে অনুকূল বাসস্থান সৃষ্টি কৰে। সেয়েহে এই অঞ্চলসমূহত নিয়মীয়া উদ্ভিদ-বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট।

আৰিষ্কাৰৰ সমান্তৰালকৈ সংৰক্ষণৰ প্রত্যাহ্বান

নতুন প্রজাতিৰ আৰিষ্কাৰ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানৰ বাবে আনন্দৰ বিষয় যদিও ইয়াৰ প্রাকৃতিক বাসস্থান সুৰক্ষিত ৰখাটোও সমানেই জৰুৰী। বনাঞ্চল ধ্বংস, অবৈধ গছ কটা, ভূমিৰ ব্যৱহাৰৰ পৰিৱর্তন আৰু জলবায়ুগত প্রভাৱে বহু উদ্ভিদ প্রজাতিৰ অস্তিত্বৰ প্রতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিব পাৰে। কোনো প্রজাতিৰ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য লাভ কৰিলেই ইয়াৰ সংৰক্ষণ নিশ্চিত নহয়; তাৰ বাবে বাসস্থানৰ সুৰক্ষা, নিয়মীয়া নিৰীক্ষণ আৰু অধিক গৱেষণাৰ প্রয়োজন।

এই ক্ষেত্রত স্থানীয় জনজাতীয় সমাজ আৰু বনাঞ্চলৰ ওপৰত নির্ভৰশীল লোকসকলৰ ভূমিকাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত প্রকৃতি-জ্ঞান আৰু বনাঞ্চলৰ সৈতে দীর্ঘদিনীয়া সম্পর্কক বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ সৈতে সংযোগ কৰিলে সংৰক্ষণৰ প্রচেষ্টা অধিক ফলপ্রসূ হ'ব পাৰে।

'ডিছপৰপছিছ ক্রিছপাটা'ৰ আৰিষ্কাৰে প্রমাণ কৰিছে যে উত্তৰ-পূৰৰ অৰণ্য এতিয়াও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানৰ বাবে বহু অজানাৰ ভাণ্ডাৰ। সেয়েহে নতুন প্রজাতিৰ সন্ধানৰ লগতে সেইবোৰৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰাটোও সমান গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰিব লাগিব। প্রকৃতিৰ এই অমূল্য সম্পদ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিলেহে ভৱিষ্যৎ প্রজন্মৰ বাবে জৈৱ-বৈচিত্রঞ্জযৰ এই ঐশ্বর্য অক্ষুণ্ণ থাকিব।

জাগীৰোডত গুলীৰ আঘাতত বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু

গুৱাহাটী: অসমৰ জাগীৰোডৰ শিলচাঙত শুকুৰবাৰে এটা বনৰীয়া হাতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। হাতীটোৰ মৃৱত দুটা গুলীৰ আঘাতৰ চিন পোৱা গৈছে। এই ঘটনাৰ পিছতে হাতীটো চোৰাং চিকাৰীৰ গুলীত নিহত হোৱাৰ সন্দেহ ঘনীভূত হৈছে।

প্রাথমিক তথ্য অনুসৰি, খাদ্যৰ সন্ধানত হাতীটো খোলাহাট বনাঞ্চলৰ পৰা জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলৰ দিশে ওলাই আহিছিল। সেই সময়তে মেঘালয়ৰ পৰা অহা বুলি সন্দেহ কৰা চোৰাং চিকাৰীয়ে হাতীটোক গুলীয়াই হত্যা কৰা বুলি আশংকা কৰা হৈছে। অৱশ্যে ঘটনাৰ প্রকৃত কাৰণ আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ পৰিচয় এতিয়াও নিদ্রিশ্চত হোৱা নাই।

খবৰ পোৱাৰ পিছতে বন বিভাগৰ বিষয়া আৰু পশু চিকিৎসকৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। হাতীটোৰ মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ নির্ধাৰণৰ বাবে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্রতিবেদনৰ অপেক্ষা কৰি আছে বন বিভাগে। প্রতিবেদন লাভ কৰাৰ পিছত প্রয়োজনীয় আইনী ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰা হ'ব।

সম্পাদকীয়

ধাননি পথাৰতো নিৰাপত্তাহীনতাহ্লু মণিপুৰত কৃষকৰ জীৱনৰ মূল্য কত?

মণিপুৰৰ উখৰুল জিলাৰ ছিনাকেইথেই গাঁৱৰ ইহাং পথাৰত ধান চপাবলৈ গৈ গুলীবিদ্ধ হ'ল ৪৯ বছৰীয়া কৃষক নিউটন মাহুং। ১২ নৱেম্বৰৰ পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩.০৫ বজাত সংঘটিত এই ঘটনাই ৰাজ্যখনৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ লগতে সাধাৰণ কৃষকৰ নিৰাপত্তাক লৈও গভীৰ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে। ধান চপোৱাৰ দৰে জীৱিকাৰ স্বাভাৱিক কামতো যদি কৃষকে প্ৰাণৰ সংশয়ত ভুগিবলগীয়া হয়, তেন্তে শান্তি আৰু স্বাভাৱিক জীৱনলৈ উভতি অহাৰ চৰকাৰী দাবীৰ বাস্তৱতা ক'ত?

গাঁও কৰ্তৃপক্ষৰ অভিযোগ অনুসৰি, লুংটেৰ পাহাৰৰ ফালৰ পৰা সন্দেহযুক্ত কুকি দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰে। এই অভিযোগৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত হোৱাটো জৰুৰী, যাতে প্ৰকৃত দোষী চিনাক্ত হয় আৰু কোনো নিৰীহ লোকক লক্ষ্য কৰি লোৱা নহয়। গাঁও কৰ্তৃপক্ষই লগতে দাবী কৰিছে যে ধান চপোৱাৰ প্ৰায় তিনি সপ্তাহ পূৰ্বেই নিৰাপত্তাৰ বাবে বি এছ এফক অনুৰোধ জনোৱা হৈছিল। তথাপি আক্ৰমণৰ সময়ত ওচৰৰ নিৰাপত্তা চকীৰ জোৱানসকলে তৎক্ষণাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে। পিছত ৰপুৰ নম্বৰ বি এছ এফ কোম্পানীসহ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দি কৃষকজনক উদ্ধাৰ কৰে। গুলীত তেওঁৰ সোঁহাতৰ আগভাগ আৰু বাঁওহাতৰ তিনিটা আঙুলি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়।

আটাইতকৈ উদ্বেগজনক কথাটো হ'ল, নিৰাপত্তাহীনতাৰ বাবে গাঁওখনৰ মাত্ৰ দুই শতাংশ কৃষিভূমিতহে ধান খেতি কৰিব পৰা গৈছে বুলি কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে। অৰ্থাৎ সংঘাতৰ মূল্য কেৱল মানুহে জীৱন আৰু সম্পত্তিৰে ভৰাই থকা নাই, কৃষি উৎপাদন আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিও ধ্বংসৰ সম্মুখীন হৈছে।

চৰকাৰে ঘটনাটোৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ পৰ্যালোচনা, আহত কৃষকৰ উপযুক্ত চিকিৎসা আৰু পথাৰত নিৰ্ভয়ে কাম কৰাৰ পৰিৱেশ নিশ্চিত কৰিব লাগিব। দোষীৰ জবাবদিহি অবিহনে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা সম্ভৱ নহয়। কৃষকৰ হাতত কাঁচি থাকিব লাগে, বন্দুকৰ গুলীৰ ভয় নহয়।

নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত ভাৰতৰ জয় সম্ভৱনে?

জন জন বিচাৰ

...✍ মদন কলিতা

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অবাধ প্ৰসাৰ এতিয়া কেৱল আইন-শৃংখলাজনিত সমস্যা হৈ থকা নাই, ই এক গভীৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক সংকটত পৰিণত হৈছে। গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ দৰে ব্যস্ত বাণিজ্যিক অঞ্চলৰ ফুটপাথতে কিশোৰৰ এটা দলে মুকলিকৈ নিচাযুক্ত গুড়ি আদান-প্ৰদান কৰা দৃশ্যই এই সংকটৰ ভয়াবহতা উদঙাই দিছে। প্ৰশ্নটো হল, আৰক্ষীৰ অভিযান, কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতো যদি নিচাৰ বজাৰ অব্যাহত থাকে, তেন্তে ভাৰতৰ ড্ৰাগছবিৰোধী যুঁজ প্ৰকৃততে সফল হৈছে নে?

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভৌগোলিক অৱস্থান এই সমস্যাৰ অন্যতম কাৰণ। ম্যানমাৰৰ সৈতে থকা দীঘলীয়া আৰু দুৰ্গম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তই ভাৰতক বিশ্বৰ অন্যতম ড্ৰাগছ উৎপাদন আৰু সৰবৰাহৰ কেন্দ্ৰ গোল্ডেন ট্ৰায়েংগলৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি ৰাখিছে। ২০২১ চনৰ সামৰিক অভ্যুত্থানৰ পিছত ম্যানমাৰত সৃষ্টি হোৱা অস্থিৰতাই এই অবৈধ ব্যৱসায়ক অধিক শক্তিশালী কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ড্ৰাগছ আৰু অপৰাধ বিষয়ক কাৰ্যালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৫ চনত ম্যানমাৰত আফিং খেতিৰ পৰিমাণ ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাই প্ৰায় ৫৩,১০০ হেক্টৰ হৈছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে হেৰইন আৰু মেথামফেটামিনজাতীয় নিচাযুক্ত বড়িৰ সৰবৰাহো বৃদ্ধি পাইছে।

জব্দৰ পৰিমাণ বাঢ়িছে কমা নাই নিচাৰ বজাৰ

অসম, মিজোৰাম আৰু মণিপুৰত আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য জব্দ হৈছে। ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা আগষ্টলৈ মিজোৰামত ৮৪৬ কোটি টকাৰো অধিক মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ, ৬৩৫টা গোচৰ ৰুজু আৰু ৯৩০জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। একে সময়তে ৰাজ্যখনত নিচাৰ ফলত ৪৫জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। অসম চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৬ চনলৈ ৰাজ্যখনত ৩,২৫৩ কোটি টকাৰো অধিক মূল্যৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য জব্দ আৰু ২৬,৫৩৭জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মণিপুৰতো এবছৰত প্ৰায় ৩,০০০ একৰ আফিং খেতি ধ্বংস কৰাৰ লগতে ৩০৭টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে।

এই পৰিসংখ্যাই চৰকাৰী অভিযানৰ ব্যাপকতা প্ৰকাশ কৰিলেও মূল সমস্যাটো সমাধান হোৱা বুলি প্ৰমাণ নকৰে। বৰং প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়-যদি নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহ নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে, তেন্তে বজাৰত ইয়াৰ সহজলভ্যতা কিয় অব্যাহত আছে? জব্দৰ পৰিমাণ আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা সফলতাৰ একমাত্ৰ মাপকাঠী হব নোৱাৰে। ড্ৰাগছৰ মূল যোগানকাৰী, বৃহৎ ব্যৱসায়ী, আৰ্থিক পৃষ্ঠপোষক আৰু তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা চক্ৰক উৎখাত কৰাটোহে প্ৰকৃত সফলতা।

মণিপুৰত সুৰক্ষাৰ আঁৰত কোন?

মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক থৌনাওজম ব্ৰিণ্ডাৰ অভিযোগে এই সমস্যাৰ আন এটা অন্ধকাৰ দিশ উন্মোচন কৰিছে। ২০১৮ চনত তেওঁ চাণ্ডেলত এজন প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই বিপুল পৰিমাণৰ হেৰইন, ২,৮০,২০০টা মেথামফেটামিন বড়ি আৰুনগদ ধন জব্দ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ গোচৰটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ ৰাজনৈতিক হেঁচা অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁ অভিযোগ আনিছিল। অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছিল।

২০২০ চনত বিশেষ আদালতে অভিযুক্তসকলক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰাৰ পিছত ব্ৰিণ্ডাই প্ৰতিবাদস্বৰূপে লাভ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক ঘু�ৰাই দিছিল। শেহতীয়াকৈ তেওঁ কেন্দ্ৰীয় আৰু মণিপুৰ চৰকাৰৰ একাংশৰ বিৰুদ্ধেও ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এই অভিযোগসমূহ এতিয়াও প্ৰমাণিত হোৱা নাই। কিন্তু এগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াই উত্থাপন কৰা এনে গুৰুতৰ অভিযোগৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত হোৱা উচিত। অভিযোগ মিছা হঙ্কলে তদন্তই সেয়া স্পষ্ট কৰিব আৰু সত্য হলে দোষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পথ মুকলি হব।

নিচাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ নে জনগোষ্ঠীয় সংঘাত?

মণিপুৰত ড্ৰাগছবিৰোধী অভিযান বহু সময়ত জনগোষ্ঠীয় সংঘাতৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ পৰিছে। পাহাৰীয়া অঞ্চলত আফিং খেতি ধ্বংসৰ অভিযানক একাংশই নিচা ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ বুলি গণ্য কৰাৰ বিপৰীতে আন একাংশই ইয়াক নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যৱস্থা বুলি অভিযোগ কৰে। ফলত অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ পৰিৱৰ্তে জনগোষ্ঠীয় সন্দেহ আৰু অবিশ্বাস বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা সৃষ্টি হৈছে।

ড্ৰাগছ ব্যৱসায় কোনো এটা জনগোষ্ঠীৰ একচেটিয়া সমস্যা নহয়। ইয়াৰ আঁৰত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ব্যৱসায়ী, বিত্তীয় পৃষ্ঠপোষক আৰু সৰবৰাহকাৰী জড়িত থাকিব পাৰে। সেয়েহে জাতিগত পৰিচয়ৰ ভিত্তিত নহয়, অপৰাধ আৰু প্ৰমাণৰ ভিত্তিত অভিযান চলোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়।

অসমত কঠোৰ অভিযানৰ পিছতো কিয় মুকলি বজাৰ?

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে ড্ৰাগছবিৰোধী অভিযানক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। জব্দ কৰা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য ৰাজহুৱাভাৰে দাহ কৰা আৰু নিচামুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্য ঘোষণা কৰাটো প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। কিন্তু পাঁচ বছৰীয়া অভিযানৰ পিছতো গুৱাহাটীৰ বাজপথত কিশোৰৰ হাতত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ উপস্থিতিয়ে বহু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে।

ইয়াৰ উপৰি আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰক লৈও উদ্বেগ আছে। ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৪ চনৰ জানুৱাৰীলৈ অসমত ২১০টাতকৈ অধিক আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি এক তথ্যভিত্তিক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছিল। ইয়াত ৮০জনাতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ নামত আইনৰ শাসন আৰু অভিযুক্তৰ ন্যায়সংগত অধিকাৰ যাতে ক্ষুণ্ণ নহয়, সেয়া নিশ্চিত কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব।

নীৰৱতা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি

ড্ৰাগছৰ অবৈধ ব্যৱসায় কেৱল সীমান্তৰ দুৰ্বলতা বা আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়। ইয়াৰ সৈতে জড়িত আছে ধনবল, ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ, ভয় আৰু সামাজিক নীৰৱতা। সাংবাদিক, সমাজকৰ্মী, আৰক্ষীৰ বিষয়া অথবা সাধাৰণ নাগৰিকে এই ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ ভয় কৰিলে অপৰাধীৰ সাহস বৃদ্ধি পাবই। গণেশগুৰিৰ ফুটপাথত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰা কিশোৰসকলক কেৱল অপৰাধী হিচাপে চোৱাটোও ভুল। তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰয়োজন চিকিৎসা, পুনৰ্বাসন, শিক্ষা আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ। নিচাসক্ত ব্যক্তিক শাস্তি দিয়াৰ লগতে নিচাৰ মূল যোগানকাৰী আৰু বিত্তীয় পৃষ্ঠপোষকসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব।

প্ৰয়োজন নতুন কৌশল আৰু ৰাজনৈতিক সদিচ্ছা

নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকৃত সফলতা লাভ কৰিবলৈ চৰকাৰে কেইটামান বিষয়ত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব। প্ৰথমতে, সৰবৰাহকাৰীৰ লগতে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ ধন যোগান ধৰা বৃহৎ চক্ৰৰ সম্পত্তি আৰু বেংক লেনদেনৰ তদন্ত কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে, ৰাজনৈতিক বা প্ৰশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতাৰ অভিযোগৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত কৰিব লাগিব। তৃতীয়তে, নিচাসক্ত লোকৰ চিকিৎসা আৰু পুনৰ্বাসনৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। চতুৰ্থতে, সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত বিকল্প জীৱিকাৰ ব্যৱস্থা কৰি আফিং খেতিৰ পৰা কৃষকসকলক আঁতৰাই আনিব লাগিব। পঞ্চমতে, ম্যানমাৰকে ধৰি চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ সৈতে সমন্বয় আৰু চোৰাংচোৰা তথ্যৰ আদান-প্ৰদান শক্তিশালী কৰিব লাগিব।

সৰ্বোপৰি, সাংবাদিক, তথ্যদাতা আৰু ড্ৰাগছবিৰোধী অভিযানত সহায় কৰা সাধাৰণ নাগৰিকৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাটো জৰুৰী।

শেষত প্ৰশ্নটো চৰকাৰৰ বাবেই নহয়, সমাজৰ বাবেও। নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কেৱল আৰক্ষীৰ বন্দুক, অভিযান আৰু জব্দৰ পৰিসংখ্যাৰে জয় কৰিব নোৱাৰি। ইয়াৰ বাবে লাগিব স্বচ্ছ প্ৰশাসন, ৰাজনৈতিক সদিচ্ছা, কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা আৰু সামাজিক সচেতনতা। যেতিয়ালৈকে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ শীৰ্ষত থকা বিত্তীয় আৰু প্ৰভাৱশালী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নহয়, তেতিয়ালৈকে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এই সমস্যা নিৰ্মূল কৰাটো অসম্ভৱ।

ড্ৰাগছবিৰোধী যুঁজত প্ৰকৃত জয় সেইদিনাহে আহিব, যিদিনা গুৱাহাটীৰ কোনো ফুটপাথত কিশোৰৰ হাতত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য দেখা নাযাব।

এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজোৰা ৰণডংকা

২৬ নৱেম্বৰৰ পৰা প্ৰতিবাদ

জন জন বিচাৰ
...✍ নতুন দিল্লী

দেশৰ নিৰ্বাচনী ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (এছআইআৰ)ক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক বিতৰ্কই নতুন ৰূপ লৈছে। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ২৬ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০ ডিচেম্বৰলৈ দেশজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ ঘোষণা কৰিছে 'পিপলছ এগেইনষ্ট এছআইআৰ' নামৰ বিভিন্ন সংগঠন আৰু কৰ্মীৰ উমৈহতীয়া মঞ্চই। আনহাতে, কৰ্ণাটকত এছআইআৰৰ সময়ত প্ৰায় ৮৪ লাখ ভোটাৰৰ অনুপস্থিতিক লৈ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত নতুন ৰাজনৈতিক বাকযুদ্ধৰ সূচনা হৈছে।

বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত প্ৰতিবাদী মঞ্চটোৱে এই কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰে। ২৬ নৱেম্বৰত সংবিধান দিৱস দিনা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰে আন্দোলনৰ শুভাৰম্ভ কৰা হব। ১০ ডিচেম্বৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ অধিকাৰ দিৱস উপলক্ষে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত গণসমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন ৰাজ্যত সমদল, ৰাজহুৱা সভা আৰু বুথ পৰ্যায়ত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হব।

আন্দোলনকাৰী মঞ্চটোৱে দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰক পুনৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰতিবাদস্থলী হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈও দাবী জনাইছে। তেওঁলোকৰ মতে, গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। ২০ ডিচেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুলৈ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে সকলো যোগ্য নাগৰিকৰ ভোটাধিকাৰ পুনৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ আহ্বান জনোৱা হব।

মঞ্চটোৰ অভিযোগ, এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত বহু যোগ্য ভোটাৰৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰাৰ আশংকা সৃষ্টি হৈছে। নিৰ্বাচন আয়োগে শেহতীয়াকৈ সাতখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা একাংশ ভোটাৰৰ পুনৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ সুযোগ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ললেও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় বুলি সংগঠনটোৱে দাবী কৰিছে। তেওঁলোকে এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰাৰ দাবীও উত্থাপন কৰিছে।

কৰ্ণাটকৰ ৮৪ লাখ ভোটাৰক লৈ বিতৰ্ক

ইফালে, কৰ্ণাটক বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা বিজেপি নেতা আৰ অশোকে বৃহস্পতিবাৰে দাবী কৰে যে ৰাজ্যখনত এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত প্ৰায় ৮৪ লাখ ভোটাৰৰ নাম সন্দৰ্ভত অনিশ্চয়তা দেখা দিছে। তেওঁৰ মতে, ইয়াৰে প্ৰায় ৬৫ লাখ লোকে বাসস্থান সলনি কৰিছে আৰু ১৯ লাখ লোকে প্ৰয়োজনীয় আবেদন জমা দিয়া নাই। এই পৰিসংখ্যাই দেশত অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ উপস্থিতিৰ দিশটোও উনুকিয়াইছে বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে।

সংবাদমেলত বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰতো বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ প্ৰৱেশ ঘটাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। অৱশ্যে এই অভিযোগৰ সমৰ্থনত তেওঁ কোনো নিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণ দাঙি ধৰা নাই। তেওঁ প্ৰায় ৩০০ বাংলাদেশী নাগৰিকক বিমানেৰে দেশৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা আৰু বেংগালুৰুত পাঁচজন পাকিস্তানী নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে। দেশত তিনি কোটি বাংলাদেশী আৰু পাকিস্তানী নাগৰিক আছে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে। এই সংখ্যাৰ স্বতন্ত্ৰ প্ৰমাণ অৱশ্যে সংবাদমেলত দাঙি ধৰা হোৱা নাই।

চৰকাৰী পৰিসংখ্যাত কি প্ৰকাশ পাইছে?

কৰ্ণাটকৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, এছআইআৰৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনৰ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল প্ৰায় ৫.৫৪ কোটি। প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত প্ৰায় ১.০৮ কোটি ভোটাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনী গণনাৰ প্ৰ-পত্ৰ লাভ কৰা হোৱা নাছিল। ইয়াৰে প্ৰায় ৬৫.৪৫ লাখক স্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰিত, ১৯ লাখক অনুপস্থিত, ১৬.৩৯ লাখক মৃত আৰু প্ৰায় ৭.০৯ লাখক একাধিক স্থানত পঞ্জীয়নভুক্ত বা একে নামৰ অন্তৰ্ভুক্তি হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছিল।

অৱশ্যে এই সকলো লোকক অবৈধ নাগৰিক বা ভুৱা ভোটাৰ বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি। নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰৱৰ্তী প্ৰক্ৰিয়াত দাবী আৰু আপত্তি নিষ্পত্তিৰ পিছত ১০ লাখৰো অধিক নতুন নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। ২৭ অক্টোবৰত প্ৰকাশিত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত ৰাজ্যখনৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৪.৫৪ কোটিৰো অধিক হয়। আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি, শুনানি আৰু পৰীক্ষণৰ অন্তত ৬১,৮৬৭ গৰাকী ভোটাৰকহে চূড়ান্ত তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছিল।

সেয়েহে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা বা অনুপস্থিত বুলি চিহ্নিত হোৱা লোকৰ সংখ্যা আৰু অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ সংখ্যা একে বুলি ধৰি লোৱাটো তথ্যগতভাৱে শুদ্ধ নহয়।

গণতন্ত্ৰত ভোটাধিকাৰৰ প্ৰশ্ন

ভোটাৰ তালিকাৰ শুদ্ধতা নিশ্চিত কৰাটো নিৰ্বাচন আয়োগৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব। একেদৰে কোনো যোগ্য নাগৰিক যাতে প্ৰশাসনিক ভুল, স্থানান্তৰ বা নথি-পত্ৰৰ সমস্যাৰ বাবে ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, সেয়াও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। এছআইআৰৰ সমৰ্থকসকলে ভুৱা, মৃত আৰু একাধিক স্থানত পঞ্জীয়নভুক্ত ভোটাৰৰ নাম আঁতৰোৱাৰ প্ৰয়োজনীয় বুলি যুক্তি দাঙি ধৰিছে। আনহাতে, বিৰোধী আৰু নাগৰিক অধিকাৰ সংগঠনসমূহে প্ৰক্ৰিয়াটোৰ স্বচ্ছতা আৰু যোগ্য ভোটাৰৰ নাম বাদ পৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে।

২৬ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হবলগীয়া দেশজোৰা প্ৰতিবাদে এই বিতৰ্কক নতুন মাত্ৰা দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া মূল প্ৰশ্ন হৈছে- ভোটাৰ তালিকা শুদ্ধ কৰাৰ নামত এজনো প্ৰকৃত ভোটাৰ যাতে তেওঁৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, সেই নিশ্চয়তা নিৰ্বাচন আয়োগে কেনেদৰে প্ৰদান কৰে।

যমুনাত মৰা মাছক লৈ দিল্লীত তীব্ৰ বিতৰ্ক



জন জন বিচাৰ
...✍ নতুন দিল্লী

দিল্লীৰ যমুনা নদীত বৃহৎ সংখ্যক মাছ মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজধানীৰ ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ছট পূজাৰ পূৰ্বে দিল্লী চৰকাৰৰ ভাবমূৰ্তি বিনষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যে কোনো অচিনাক্ত চক্ৰই পৰিকল্পিতভাৱে যমুনা নদীত মৰা মাছ পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দিল্লী চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন আৰু বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগে। এই সন্দৰ্ভত বিভাগটোৰে ছোনিয়া বিহাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ দাবী জনাইছে।

বিভাগটোৰ অভিযোগ অনুসৰি, ছট পূজাৰ পূৰ্বে যমুনা নদীক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে নেতিবাচক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই ঘটনা সংঘটিত কৰা হব পাৰে। অৱশ্যে এই অভিযোগৰ সত্যতা এতিয়াও আৰক্ষীৰ তদন্তৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নাই।

উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ ছোনিয়া বিহাৰ অঞ্চলৰ ৰাজিৰাবাদ দলঙৰ সমীপত যমুনা নদীৰ পানীত বহু মাছ মৃত অৱস্থাত পৰি থকা দেখা যায়। ঘটনাৰ দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰাৰ পিছতে ব্যাপক চৰ্চাৰ সৃষ্টি হয়। ভাই�ৰেল হোৱা ভিডিঅত নদীৰ পানীত অসংখ্য মৰা মাছ ওপঙি থকা দেখা গৈছে।

আনহাতে, এই ঘটনাই যমুনাৰ পানীৰ গুণগত মান আৰু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰাক লৈ পুনৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হল, মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে এই একেটা অঞ্চলতে যমুনা নদীত বৈদ্যুতিক ক্ৰুজ সেৱাৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল। তাৰ পিছতে মাছৰ মৃত্যুৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাত নদীৰ পানীৰ বাস্তৱিক অৱস্থাক লৈ নতুনকৈ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে।

এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, মাছৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি? নদীৰ পানীৰ প্ৰদূষণ নে আন কোনো কাৰণত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে? আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰু পানীৰ নমুনা পৰীক্ষাৰ ফলাফলেহে এই সন্দৰ্ভত স্পষ্ট ছবি দাঙি ধৰিব পাৰিব।

গাখীৰৰ প্ৰতি লিটাৰত ২ৰ পৰা ৪ টকা পৰ্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি

জন জন বিচাৰ
...✍ গুৱাহাটী

দেশৰ সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ মূৰত পুনৰ পৰিল মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা। ১২ নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আমূল আৰু মাডাৰ ডেইৰীয়ে নিজৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পেকেট গাখীৰৰ দাম প্ৰতি লিটাৰত ২ৰ পৰা ৪ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিছে। দুয়োটা বৃহৎ দুগ্ধ প্ৰতিষ্ঠানৰ এই সিদ্ধান্তৰ ফলত দেশৰ লাখ লাখ পৰিয়ালৰ দৈনন্দিন খাদ্য ব্যয় বৃদ্ধি পোৱাটো নিশ্চিত।

আমূল ব্ৰেণ্ডৰ অধীনত দুগ্ধজাত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা গুজৰাট কো-অপাৰেটিভ মিল্ক মাৰ্কেটিং ফেডাৰেচনে (জি চি এম এম এফ) কেইবাবিধো গাখীৰৰ দাম সংশোধন কৰিছে। নতুন নিৰিখ অনুসৰি, তিনি শতাংশ চৰ্বিযুক্ত আমূল তাজাৰ প্ৰতি লিটাৰত ২ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আনহাতে, ছয় শতাংশ চৰ্বিযুক্ত আমূল গোল্ডৰ দাম প্ৰতি লিটাৰত ৪ টকা বৃদ্ধি পাইছে। আমূল গোল্ডৰ ক্ষেত্ৰত এই বৃদ্ধিৰ হাৰ প্ৰায় ৫.৫ শতাংশ।

জি চি এম এম এফে জনোৱা অনুসৰি, গাখীৰ উৎপাদন আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হৈছে। পশুখাদ্য, সেউজীয়া আৰু শুকান ঘাঁহ, তেলৰ খলিহৈ, মাকৈ, গুড়, পেকেজিং সামগ্ৰী আৰু ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে উৎপাদন ব্যয় বঢ়াইছে। ইয়াৰ উপৰি গুজৰাটসহ দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কম আৰু অনিয়মীয়া ববষুণৰ ফলতো দুগ্ধ উৎপাদনত প্ৰভাৱ পৰিছে।

সংস্থাটোৱে দাবী কৰিছে যে যোৱা এবছৰত সদস্য দুগ্ধ সমবায়সমূহে গাখীৰ উৎপাদক কৃষকসকলক দিয়া ক্ৰয়মূল্য ৪ৰ পৰা ৫ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিছে। কৃষকসকলক উপযুক্ত মূল্য প্ৰদান অব্যাহত ৰখাৰ লক্ষ্যৰেই গ্ৰাহকৰ বাবে দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছে।

GAURANSHI
INDUSTRIES

Gunika™

Purity in Every Drop, Nature in Every Product.

100% NATURAL



TEA

NAME	MAKHANA (FOX NUT SUPERFOOD)	ASSAM CTC TEA	ASSAM CTC TEA
SIZE	200gm	250gm	100gm

HONEY



NAME	MORINGA HONEY	TULSI HONEY
SIZE	200gm	200gm



NAME	MUSTARD HONEY	LITCHI HONEY	WILD FOREST HONEY
SIZE	200gm	200gm	200gm

RAW & UNPROCESSED | PURE & NATURAL | DIRECTLY FROM OUR FARMS | TRUSTED BY THOUSANDS

3rd Floor, IIT Road,
Jayguru, Amingaon,
Kamrup, Assam - 781031, India

Contact :
+91-88224 20619

E-Mail :
gauranshiind@gmail.com
www.gauranshiindustries.com

VOICE OF ALL, FOR ALL
WEEKLY
JAN JAN VICHAR
Guwahati, Friday, 13 November 2026





9.25 Lakh Indians Acquire Foreign Citizenship In 5 Years

India tops OECD list of citizenship seekers; Canada, US and Australia emerge as major destinations, raising questions over talent retention and opportunities at home

Jan Jan Vichar
...✍New Delhi

The growing number of Indians settling permanently overseas has once again brought the issue of migration into focus. More than 9.25 lakh Indians acquired citizenship in member countries of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) between 2020 and 2024, placing India at the top of the list of countries whose citizens obtained foreign nationality during the period.

According to the OECD's International Migration Outlook 2026, a total of approximately 925,000 Indians became citizens of OECD member countries over these five years. This represents an increase of around 41 per cent compared with the 2015–2019 period, when approximately 6.5 lakh Indians acquired citizenship in these countries.

The trend reflects the growing presence of Indian communities across developed economies and the increasing number of people choosing to make their lives overseas. In 2024 alone, more than 2.30 lakh Indians acquired citizenship in OECD countries.

Canada remains the leading destination

Canada accounted for the largest number of Indian citizenship acquisitions in 2024, with 87,320 Indians becoming Canadian citizens. The United States followed with 48,820, while Australia recorded 28,969 and the United Kingdom 24,888.

Canada has remained particularly attractive to Indian migrants because of its established Indian community, employment opportunities and immigration pathways. The United States continues to attract professionals, students and skilled workers, while Australia and the United Kingdom remain important destinations for Indian families and young professionals.

The figures also underline how migration has evolved. For many Indians, moving abroad is no longer limited to temporary employment or higher education. It increasingly involves long-term settlement, family relocation and eventual acquisition of citizenship.

India remains a major source of global migration

The OECD report also highlights India's position as a major source of international migrants. However, the number of Indians moving to OECD countries declined from approximately 6.07 lakh in 2023 to 4.94 lakh in 2024, a fall of 19 per cent.

Indian students continue to form a significant part of the overseas population. Around 8.3 lakh Indian students were studying in OECD member countries, reflecting the continuing demand for international education and professional opportunities.

At the same time, immigration policies in several developed countries are becoming more restrictive. Changes in student visa rules, work permits and permanent residency requirements have made migration more challenging for many applicants.

A challenge for India's future

The growing number of Indians acquiring foreign citizenship presents both opportunities and concerns. The overseas Indian community contributes to India's international standing through business, technology, research, investment and remittances. Many Indians have also established successful careers in some of the world's most competitive economies.

However, the steady movement of people towards permanent settlement abroad raises an important question: why are so many Indians choosing to build their long-term future outside their own country?

Better employment prospects, higher salaries, quality education, research facilities, professional growth and improved living standards are among the factors that influence migration decisions. While citizenship figures alone cannot establish the reasons behind every individual's decision, they provide an indication of the scale of long-term settlement.

For India, the challenge is not to discourage people from seeking opportunities abroad. Rather, it is to create an environment where skilled professionals, young graduates, researchers and entrepreneurs also find attractive opportunities at home.

The OECD figures are therefore more than just migration statistics. They offer a reminder that India's development will depend not only on producing a skilled workforce but also on creating conditions that encourage talent to contribute to the country's own economic and social progress.

Guwahati Celebrates Diwali with Rs 3.9 Crore Liquor Sales

Jan Jan Vichar
...✍Guwahati

Diwali festivities in Guwahati witnessed liquor sales worth approximately Rs 3.9 crore in just two days, highlighting the scale of alcohol consumption during the festive season. According to figures released by the Assam Excise Department, liquor worth this amount was sold across the city on November 8 and 9. The figures offer a glimpse into the city's festive spending patterns, with liquor purchases accounting for a substantial volume of business during the celebrations. However, the latest sales total marks a decline compared with the corresponding Diwali period in previous years. Guwahati had recorded liquor sales worth Rs 4.80 crore during Diwali in 2024, while the figure stood at Rs 6.20 crore in 2023. The latest reported amount of Rs 3.9 crore is considerably lower than both these figures, although the absence of comparable data for 2025 makes a direct year-on-year assessment difficult.

Interestingly, the Excise Department data also indicates that liquor sales on November 7 were higher than those recorded on November 8. However, the exact sales figure for November 7 was not immediately available. The latest figures have brought attention to the changing pattern of festive consumption in Assam's largest city. While Diwali traditionally drives increased commercial activity across several sectors, liquor sales remain one of the indicators of consumer spending during the celebrations. The department's figures cover liquor sales across Guwahati on the specified dates.

THE WEEK IN BRIEF

Cabinet Approves Merger of Sanskrit College with Nalbari University

GUWAHATI: The Assam Cabinet has approved the merger of Krishna Kanta Handique Government Sanskrit College in Guwahati with Kumar Bhaskar Varma Sanskrit and Ancient Studies University in Nalbari, with the college set to shift entirely to the university campus.

Chief Minister Himanta Biswa Sarma said the decision was taken due to low student enrolment, with only 65 students currently enrolled in the Guwahati college. He said existing students would be accommodated in the university, while the college's teaching staff would be absorbed as university professors.

The Chief Minister also announced that another educational institution would be named after noted Assamese scholar Krishna Kanta Handique.

Arunachal Opens Geothermal Powered Drying Facility in Dirang

DIRANG : Arunachal Pradesh Science and Technology Minister Dasanglu Pul on Tuesday inaugurated a geothermal-powered drying facility at Dirang in West Kameng district to reduce post-harvest losses and improve farmers' incomes.

The facility uses natural geothermal heat to dry and preserve locally produced kiwi, apples, persimmons and yak meat, helping extend their shelf life and improve market value. It has been funded by the Union Ministry of Earth Sciences with additional support from the state government.

Norwegian Ambassador to India May-Elin Stener, Dirang MLA Phurpa Tsering and scientists and experts from India, Norway and Iceland attended the inauguration.

Pul said the project would help translate scientific research into practical benefits for farmers and promote renewable energy-based agricultural practices. She also urged the Centre to issue the sanction order for the approved Seismic Microzonation Project, citing Arunachal Pradesh's vulnerability to earthquakes as a Seismic Zone V state.

Nayanmoni Files Nomination for Assam Sahitya Sabha Polls



GUWAHATI: Nayanmoni Choudhury on Wednesday filed his nomination for the post of General Secretary of the Assam Sahitya Sabha, intensifying preparations for the upcoming election.

Choudhury submitted his nomination papers at the Sabha's headquarters, Bhagawati Prasad Barua Bhawan, in Guwahati. He was accompanied by representatives of several Sabha branches and literary enthusiasts from different districts.

Around 10 vehicles were part of his convoy, while a large number of supporters gathered at the central office during the nomination process.

BJP Sweeps Tripura Civic Polls Before Voting

Wins 77 Seats Unopposed

Jan Jan Vichar
...✍Agartala



The Bharatiya Janata Party (BJP) has secured a major early advantage in Tripura's upcoming civic elections, winning 77 seats unopposed across five urban local bodies even before polling begins. The outcome has intensified the political contest in the state, with the opposition CPI(M) alleging intimidation and coercion of its candidates during the nomination process.

According to the State Election Commission, the BJP candidates were elected unopposed after the completion of scrutiny of nomination papers. The five urban local bodies where the party secured these victories are Mohanpur, Kamalpur, Jirania, Ranirbazar and Santirbazar.

Elections are being held for 345 seats across 21 urban local bodies, including the Agartala Municipal Corporation. With 77 seats already decided, polling will now take place for the remaining 268 seats on November 27. Counting of votes is scheduled for December 3.

State Election Commissioner P.K. Chakraborty said that 810 candidates are contesting the remaining seats. The BJP has fielded the highest number of candidates at 342, followed by the CPI(M) with 218 and the Congress with 201, setting the stage for a triangular contest among the principal political parties.

However, the BJP's unopposed victories have triggered a political controversy. CPI(M) state secretary Jitendra Chaudhury alleged that opposition candidates in Ambassa, Dhalai district, were threatened and intimidated, with some reportedly facing attacks at their residences and being forced to withdraw their nominations. The State Election Commission, however, rejected the allegations. Chakraborty said the commission had sought reports from the Dhalai District Magistrate and Superintendent of Police following complaints of forced withdrawals. According to the reports received, no such incidents had taken place in Ambassa or elsewhere in Dhalai district.

The controversy has brought the issue of electoral competition and the political environment in Tripura into focus ahead of the remaining polling. While the BJP enters the next phase with 77 seats already secured, the opposition faces the challenge of converting the remaining electoral contest into a credible fight.

The November 27 polling will therefore be crucial in determining the balance of power across Tripura's urban local bodies.

Left and Congress Unite Against BJP

The Left Front and the Congress have joined hands to challenge the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) in Tripura's civic elections, seeking to consolidate anti-BJP votes and prevent a division of the opposition vote. The alliance assumes particular significance as the state prepares for elections to 21 urban local bodies, including the politically important Agartala Municipal Corporation (AMC), on November 27.

The decision to contest the elections together was announced by CPI(M) leader and Leader of the Opposition in the Tripura Assembly, Jitendra Chaudhury. He said the final seat-sharing arrangement would be completed after Congress leaders return from New Delhi, where they are attending an INDIA bloc rally against the Chief Election Commissioner.

As part of the proposed arrangement, the CPI(M) has already filed nomination papers for 26 of the 51 wards of the Agartala Municipal Corporation, leaving the remaining 25 wards for the Congress. The understanding reflects an attempt by the two parties to put aside their political differences and build a united electoral challenge against the BJP.

The opposition alliance comes at a crucial moment in Tripura politics. The BJP has already secured 77 seats unopposed across five urban local bodies, including Mohanpur, Kamalpur, Jirania, Ranirbazar and Santirbazar, ahead of the November 27 polling.

Bhim-MIM Alliance Sets UP Politics Abuzz

Jan Jan Vichar
...✍Lucknow

A new political alliance has stirred the electoral waters of Uttar Pradesh ahead of the 2027 Assembly elections. The All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM), led by Asaduddin Owaisi, and Chandrashekhar Azad's Azad Samaj Party (Kanshi Ram) have joined hands to form the 'Samajik Parivartan Morcha', with Azad being projected as the alliance's chief ministerial candidate.

The formation of the alliance has raised a crucial political question: will this proposed Muslim-Dalit combination emerge as a serious challenge to the BJP, or will it primarily eat into the traditional vote base of the Samajwadi Party (SP) and Congress? The two leaders announced the alliance at a joint press conference in Lucknow on Thursday, November 12. Owaisi expressed confidence that the new platform would emerge as a strong political alternative and prevent the BJP from returning to power for a third consecutive term. Azad, meanwhile, rejected the description of the alliance as merely a 'third front', calling it the 'Samajik Parivartan Morcha' and asserting that it could become the first choice of people seeking social and political change.

However, the electoral arithmetic presents a more complicated picture. Political observers believe that the alliance could pose a greater challenge to the INDIA bloc, particularly the SP and Congress, than to the BJP. Its potential support base largely comprises Muslims and Jatav Dalits-two communities that played a significant role in strengthening the SP-led opposition in the 2024 Lok Sabha elections. Together, these communities account for a substantial share of Uttar Pradesh's electorate. Analysts suggest that even a modest shift in their voting preferences could influence the outcome in several closely contested constituencies across western and eastern Uttar Pradesh. Some assessments put the new alliance's potential vote share at around five per cent, a figure that could prove decisive in a state where electoral margins are often narrow.



A challenge to SP's PDA strategy?

The alliance could also complicate the SP's efforts to consolidate its PDA(Pichhda, Dalit and Alpsankhyak) social coalition. Owaisi's emphasis on Muslim political representation may appeal to sections of young Muslim voters who feel that established opposition parties have not given the community adequate leadership opportunities.

AIMIM has repeatedly argued that Muslims, who constitute around one-fifth of Uttar Pradesh's population, remain inadequately represented in the political power structure. The party has questioned the reluctance of mainstream parties to offer meaningful positions of authority to Muslim leaders.

At the same time, Chandrashekhar Azad brings a distinct Dalit political identity and a growing profile, particularly among sections of younger voters. His presence could potentially attract voters who are dissatisfied with the existing political choices, including sections of the BSP's traditional support base.

For the BJP, the emergence of the alliance could create opportunities if opposition votes are divided. However, whether the new formation can translate its social support claims into votes and seats remains uncertain.

Past electoral performance raises questions

The previous electoral record of the two parties highlights the scale of the challenge before them. In the 2022 Uttar Pradesh Assembly elections, AIMIM contested 95 seats but failed to win any, securing approximately 0.49 per cent of the vote. Azad Samaj Party also failed to open its account, polling around 0.13 per cent. The alliance will therefore have to demonstrate that its combined political appeal can go beyond the individual vote shares of its constituent parties. A joint platform, a common campaign strategy and the selection of credible candidates will be crucial to its electoral prospects. Owaisi had reportedly approached the Samajwadi Party several times with an offer of an alliance, but SP president Akhilesh Yadav did not accept the proposal. Following the refusal, AIMIM moved towards an understanding with Chandrashekhar Azad, who is seeking to expand his party's political footprint in Uttar Pradesh.

The announcement has already triggered criticism from Congress leaders. Congress leader Vijay Thottathil described the new formation as a potentially 'destructive front' and alleged that it could divide secular votes, indirectly benefiting the BJP. He also repeated the charge that AIMIM acts as the BJP's 'B-team'-an allegation that Owaisi and his party have consistently rejected.

The real test will be at the ballot box

The BJP, meanwhile, is seeking to retain its political advantage amid a divided opposition landscape. The SP and Congress will have to assess whether the new alliance can weaken their electoral coalition, while the BSP may also face pressure in constituencies where Dalit voters remain politically decisive. Yet, it would be premature to conclude that the new alliance will automatically damage the INDIA bloc or benefit the BJP. Its actual impact will depend on candidate selection, local equations, campaign issues, voter mobilisation and the extent to which Muslim and Dalit voters respond to its political appeal.

The 'Samajik Parivartan Morcha' has entered the political arena with an ambitious claim of changing Uttar Pradesh's power equation. But the central question remains: can the Bhim-MIM partnership emerge as an independent force, or will it become a vote-splitter in a contest dominated by the BJP and the INDIA bloc? The answer will begin to take shape as the 2027 election campaign gathers momentum.

Part of Madhubani Collectorate to Be Auctioned

Varun Kumar, Patna : In an unusual development, a portion of the Madhubani District Collectorate in Bihar, which houses key administrative and law enforcement offices, is set to go under the hammer on November 26 over unpaid dues of Rs 4.17 crore to a private company. The auction proceedings are set to continue after a Supreme Court Bench comprising Justice Arvind Kumar and Justice Vipul M. Pancholi dismissed the Bihar government's Special Leave Petition (SLP) seeking a stay on the execution proceedings ordered by the lower court. Following the Supreme Court's refusal to intervene, the Madhubani District and Sessions Court issued a revised sale proclamation, fixing November 26 for the auction of approximately 10 kattha of land and a two-storey building located in the southern portion of the Collectorate complex. The auction is intended to recover the outstanding amount of Rs 4.17 crore.

A senior district administration official told The Indian Express that the matter falls under the jurisdiction of the Industry Department and that the district administration has no direct role in it. Asked why a portion of the Collectorate had been selected for auction, the official reportedly said, "It is because the Collectorate is the face of the government." A senior Industry Department official said the department would need approval from the Finance Department to clear the outstanding amount before the deadline.

EDITORIAL

Terrorism in J&K Contained, Not Defeated

The killing of two Special Police Officers (SPOs) in Kishtwar and the attack on a CRPF party in Kulgam within two days expose the continuing threat of terrorism in Jammu and Kashmir. These incidents are a grim reminder that, despite significant security gains, militancy has been contained but not eliminated. The murder of the two SPOs, reportedly on their way to join duty at an Army camp in the remote Marwah sector, bears the hallmarks of a terrorist attack. The disappearance of their service weapons adds to the suspicion. Similarly, the assault on CRPF personnel in Kulgam shows that militant groups retain both the intent and capability to strike. Security forces have achieved notable successes in eliminating terrorists and disrupting militant networks. Yet, isolated attacks reveal that underground support systems and pockets of militant activity remain. Difficult mountainous terrain continues to provide opportunities for armed groups to hide, regroup and operate. The response must go beyond counter-insurgency operations. Better coordination among security agencies, reliable intelligence and sustained action against militant networks are essential. Equally important is winning the confidence of local communities. Residents of vulnerable areas must be partners in maintaining peace, not merely recipients of security measures. The government must ensure that those responsible for these attacks are brought to justice. Political assurances are important, but they must be backed by effective action. Jammu and Kashmir has made considerable progress towards peace, but these attacks show that the journey is far from over. Terrorism must not only be contained; its networks, support structures and ability to regenerate must be dismantled.

The Battle for UP's Educational Future

Jan Jan Vichar

...✍Dr. Patanjali Mishra

Chief Minister Yogi Adityanath's recent warning to young people against the Samajwadi Party (SP), which he has portrayed as an adversary of education, is more than a routine exchange of electoral rhetoric. It revives a fundamental question about the governance of Uttar Pradesh: whether education and public employment have been insulated from political patronage, administrative irregularities and institutional failures. His pointed remarks bring renewed attention to recruitment controversies, examination paper leaks and the condition of schools during Akhilesh Yadav's tenure, while prompting a comparison between the two administrations' approaches to education and employment. At its heart, the debate concerns not merely political claims, but the credibility of the institutions entrusted with shaping the aspirations of the state's youth.

During the Akhilesh Yadav government, public recruitment processes repeatedly faced allegations of irregularities, while examination-related controversies fueled uncertainty among aspiring candidates. For many young people, the pursuit of government employment became a prolonged test of patience, with the promise of opportunity often overshadowed by concerns over fairness and transparency. Questions were also raised about school infrastructure, teacher appointments and the overall functioning of the education system. When recruitment procedures become mired in controversy, the consequences extend beyond individual disappointments: they undermine public confidence, particularly among candidates who have invested years in preparation. Such failures, where established, represent not merely administrative shortcomings but setbacks to the aspirations of an entire generation.





Under Yogi Adityanath, the state government has emphasized transparency in public recruitment and sought to address concerns associated with earlier practices. According to figures cited by the government, more than 950,000 jobs have been provided without recommendations, while efforts are under way to facilitate another 100,000 appointments. These figures form a central part of the administration's case that recruitment has become more transparent and accessible. Yet, the significance of this claim rests not on the headline number alone, but on the integrity of the selection process, the equitable distribution of opportunities and the verifiability of official records. Efforts to improve examinations, appointments and educational infrastructure likewise merit assessment against measurable outcomes rather than political assertions alone.

In Uttar Pradesh, the stakes are particularly high. The state's large young population makes education and employment central to its social and economic prospects, while government jobs continue to represent a measure of stability and upward mobility for many households. A credible recruitment system rewards merit; an opaque one breeds disillusionment and erodes confidence in public institutions. Yogi Adityanath's remarks seek to draw a sharp distinction between the previous administration's record and his government's stated approach. The opposition may characterize this as political point-scoring, but the underlying concerns cannot be dismissed merely because they have resurfaced during an election cycle. Equally, allegations concerning the past must be examined against documented evidence rather than accepted solely on the strength of partisan rhetoric.

No administration can reasonably claim to be beyond scrutiny. Despite the Yogi government's emphasis on recruitment transparency, unemployment remains a pressing concern, and many young people continue to look towards private-sector employment or self-employment. Government job announcements and appointment figures, though significant, do not by themselves establish that the broader employment challenge has been resolved. The quality of schooling, the availability of skilled employment and the prevention of examination fraud require sustained institutional attention. The relevant question, therefore, is whether the measures introduced have delivered durable improvements–and whether those improvements can be demonstrated through verifiable data.

Making education and employment subjects of political debate is neither inherently inappropriate nor undesirable. The danger arises when substantive policy questions are reduced to accusations and counter-accusations. Paper leaks compromise more than individual examinations; they weaken confidence in the institutions that administer them. Transparent recruitment, accountable governance and functioning schools, conversely, provide the foundations on which public trust can be rebuilt. Ultimately, education and employment transcend party affiliations. Their outcomes shape the state's future and determine whether young people can translate aspiration into opportunity. Yogi Adityanath's remarks have brought the contrast between the two administrations back into public discussion, but the credibility of either government must rest on evidence, implementation and outcomes. Remembering past controversies is important; scrutinizing present-day claims is equally necessary. The future of education in Uttar Pradesh will be determined not by the force of electoral rhetoric, but by the establishment of institutions that are transparent, accountable and capable of delivering meaningful opportunities.

Bihar Government Orders Strict Safety Measures for Chhath Puja

Jan Jan Vichar
...✍Varun Kumar, Patna

The Bihar Disaster Management Department has directed all districts to implement strict safety measures during the four-day Chhath Puja festival, scheduled from November 13 to 16. The directives include a ban on firecrackers near Chhath ghats and private boat operations to prevent accidents and ensure the safety of devotees, officials said.



According to a statement issued by the department on Monday, District Magistrates have been instructed to identify potentially dangerous ghats and barricade them to prevent devotees from entering unsafe areas. Adequate security personnel and volunteers must also be deployed at all major ghats.

Divers, Motorboats & Rescue Equipment to Be Deployed

The department has directed district administrations to station trained divers, swimmers, motorboats and essential life-saving equipment at river ghats. Medical teams, ambulances and Quick Medical Response Teams (QMRTs) must remain on standby throughout the festival to respond to emergencies.

Adequate Lighting and Electrical Safety

The guidelines also emphasise adequate lighting arrangements at ghats and approach roads. All electrical installations must be inspected in advance to prevent incidents of electrocution. District administrations have also been asked to ensure continuous public announcements through loudspeakers and keep district control rooms operational round the clock during the festival.

Measures to Prevent Stampedes and Panic

To prevent panic and stampede-like situations, District Magistrates have been instructed to prepare comprehensive disaster management and communication plans. Coordination meetings with Chhath Puja committees must be held to ensure proper arrangements and effective crowd management.

The department has further stressed the need for continuous monitoring and coordination among all concerned departments throughout the festival.

Four-Day Festival Begins on November 13

Chhath Puja, dedicated to the Sun God and Chhathi Maiya, is one of Bihar's most significant religious festivals. The four-day celebration will begin on November 13 with the traditional 'Nahay Khay' ritual and conclude on November 16 with the offering of prayers to the rising Sun.

Observed during the Hindu month of Kartik, six days after Diwali, the festival involves devotees observing rigorous fasts and offering prayers to the setting and rising Sun for the well-being, health and prosperity of their families. The state government's directives aim to ensure that devotees can observe the festival safely and peacefully.

Anant Singh Plans Grand Feast for Daughter Shivangi's Wedding, 4 Lakh Guests Expected

Jan Jan Vichar
...✍Varun Kumar, Patna

Mokama MLA Anant Singh is preparing for a grand celebration to mark the wedding of his daughter, Shivangi Singh, with Rishikesh Kumar on November 25. The wedding ceremony will be held at Singh's ancestral home in Ladma village, where preparations are underway on a massive scale.





The organisers are reportedly making arrangements to accommodate and serve food to as many as four lakh people. The scale of the event is expected to make it one of the major wedding celebrations in the region. Artisans from Mau in Uttar Pradesh have been engaged to construct the wedding pandal and the stage for the varmala ceremony. The main pandal is expected to be completed by November 20. A separate enclosure is also being prepared for VVIP guests. A 100-foot-long cemented stage is being constructed for the bride and groom. According to the arrangements described, around 150 quintals of decorative material will be used to adorn the stage, where Shivangi and Rishikesh will exchange garlands.

New Home Being Prepared in Bihta

After the wedding, the groom's family will move to Ramakrishna Nagar in Bihta, which will become Shivangi's new home. A new house is being constructed there, and wedding-related rituals and celebrations are also planned at the residence. The wedding procession, or baraat, will travel from Bihta to Anant Singh's ancestral village in Ladma, where the marriage rituals will take place.

Political Leaders and Film Personalities Invited

Anant Singh has said that invitations are being extended to prominent personalities from politics and the entertainment industry. Leaders from both the ruling alliance and the Opposition have been invited, along with personalities from different parts of the country.

Singh said that everyone had been invited, including people from outside Bihar and even Pakistan. He added that there was no distinction between the ruling side and the Opposition at a wedding and that Prime Minister Narendra Modi would also be sent an invitation.

Around three dozen film and entertainment personalities are reportedly on the guest list. Names mentioned include Sonu Sood, Manoj Tiwari, Maithili Thakur, Akshara Singh and Pawan Singh. Their attendance, however, has not been independently confirmed.

Supreme Court Directs Anant Singh to Surrender by December 1

The wedding celebrations will be followed by a significant legal development for the Mokama MLA. Six days after the wedding, Anant Singh is required to surrender by December 1 in connection with the Dular Chand Yadav murder case, following a direction from the Supreme Court.

Chhath Puja

The Ancient Sun Worship Tradition That Became Bihar's Cultural Identity

Jan Jan Vichar
...✍Patna

As millions of devotees gather along riverbanks, ponds and other water bodies to offer prayers to the setting and rising sun, Chhath Puja once again brings alive one of India's most distinctive religious and cultural traditions. Deeply rooted in Bihar, the four-day festival has travelled far beyond the state's boundaries, becoming a global symbol of faith, discipline and devotion.

But how did Chhath become such an integral part of Bihar's cultural identity? Its origins are associated with ancient traditions of sun worship, with popular religious narratives tracing its roots to the Mahabharata and Ramayana.



The grand festival of Chhath Mahaparv was also featured in Doordarshan's blockbuster television shows Mahabharat and Ramayan. In these serials, Sita and Draupadi were portrayed worshipping Mother Ganga and the Sun God.

Karna & Mahabharata connection

One of the most widely known legends associated with Chhath Puja revolves around Karna, the son of Surya, the Sun God, and Kunti in the Mahabharata. According to popular belief, Karna regularly worshipped the Sun God while standing waist-deep in water and offered prayers at sunrise. Known for his extraordinary generosity, he also distributed gifts and donations to the needy.

Karna was made the king of Anga Desh by Duryodhana. The ancient Anga region is traditionally associated with parts of present-day Bihar, particularly the Bhagalpur and Munger areas.""His devotion to the Sun God is believed to have inspired people in the region to adopt similar practices. Over generations, these traditions became associated with the observance of Chhath, although the precise historical origins of the festival remain uncertain.

The Ramayana connection: Sita's worship in Munger

Another popular tradition connects Chhath with the Ramayana. According to local religious belief, after their return from Lanka, Lord Rama and Goddess Sita visited the ashram of sage Mudgal in the present-day Munger region of Bihar. It is believed that on the sixth day of the lunar month of Kartik, Sita observed a fast and offered prayers to the Sun God. A site associated with this tradition is the Sita Charan Temple, located on the Ganga in Munger. The story has become an important part of the region's religious heritage, strengthening the association between Chhath and Bihar.

A festival unlike any other

One of the most distinctive features of Chhath is the offering of arghya to both the setting and the rising sun. Unlike many other Hindu festivals, worshippers first offer prayers to the setting sun before returning to the water bodies the following morning to welcome the rising sun.

The festival is observed over four days:

Nahay-Khay: Devotees take a ritual bath and prepare a simple, traditional meal.

Kharna: After fasting throughout the day, devotees break their fast after evening prayers and distribute prasad.

Sandhya Arghya: Devotees gather at riverbanks and ponds to offer prayers to the setting sun.

Usha Arghya: The festival concludes with offerings to the rising sun, followed by the breaking of the fast.

The strict discipline, cleanliness, simplicity and devotion associated with these rituals make Chhath a remarkable expression of collective faith.

Chhathi Maiya and the worship of nature

Chhath is dedicated to Surya Dev and Chhathi Maiya. According to popular religious beliefs, Chhathi Maiya is associated with the protection of children, family prosperity and well-being. The festival also reflects a deep connection with nature. Bamboo baskets, seasonal fruits, sugarcane, coconuts and other locally available agricultural produce form an essential part of the offerings. There is no elaborate display of rituals or expensive decorations. Devotees place their faith in natural offerings, discipline and sincere prayers.



Printed & Published by Purvanchal Prints, GMCH Road, Harbala Market, Bhangagarh, Guwahati-781005 Contact: 69001 26012
Email : Official.janjanvichar@gmail.com,Website : www.janjanvichar.in ● Executive Editor : Subhash Kumar Choudhary ● Editor : Dhaneshwar Choudhary